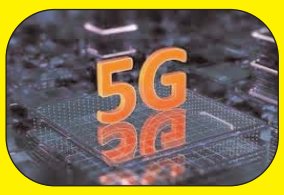

देश में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या नवंबर 2025 में एक अरब के पार

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोकशक्ति

मोदी 3 जनवरी 2026 को पिपरावा के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-62 > अंक - 08 | रायपुर | गुरूवार 1 जनवरी 2026 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2026-28

केंद्र सरकार ने पेन किलर टेबलेट पर लगाया तत्काल बैन, मार्केट में अब नहीं मिलेगी

नई दिल्ली. एजेंसी

केंद्र सरकार ने नाइमेसुलाइड पेनकिलर को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है. सरकार ने 100 mg से अधिक मात्रा वाली नाइमेसुलाइड की सभी ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. यह फैसला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत लिया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ज्यादा डोज वाली यह दवा मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है, जबकि इसके सुरक्षित विकल्प पहले से बाजार में उपलब्ध हैं.

क्यों लगाया गया नाइमेसुलाइड पर बैन?

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 100एमजी से अधिक डोज वाली नाइमेसुलाइड दवाएं इंसानों के लिए जोखिमपूर्ण साबित हो सकती हैं. नाइमेसुलाइड एक नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (एनएसएआईडी) है, जिस पर लिवर टॉक्सिसिटी और अन्य गंभीर दुष्प्रभावों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं।

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए 224 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि जारी की

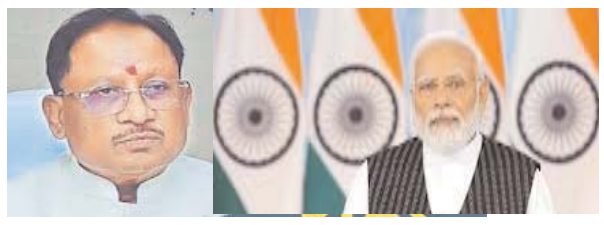

पीआईबी।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की अनटाइड अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में ?224.5762 करोड़ की राशि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जारी की है। यह अनुदान राज्य की 11279 पात्र ग्राम पंचायतों, 138 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 26 पात्र जिला पंचायतों के लिए है। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त वर्ष के अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किए जाते हैं। अनटाइड अनुदानों का उपयोग पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस विषयों के अंतर्गत, वेतन और अन्य स्थापना व्ययों को छोड़कर, स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। टाइड अनुदानों का उपयोग (क) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव के लिए किया जा सकता है, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन और उपचार, विशेष रूप से मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन शामिल होना चाहिए, और (ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है।

मोदी कैबिनेट की बैठक में 20,668 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी

महाराष्ट्र में 6-लेन ग्रीन फील्ड नासिक-सोलापुर कॉरिडोर बनेगा

नईदिल्ली,एजेंसी

केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक बुधवार 31 दिसंबर को आयोजित की गई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर भी लगाई गई. इन फैसलों के तहत महाराष्ट्र में 6-लेन ग्रीनफील्ड नासिक-सोलापुर कॉरिडोर (कुल लंबाई: 374 किमी) को मंजूरी दी गई. इस प्रोजेक्ट की लागत 19,142 करोड़ रुपए बताई जा रही है. इसके अलावा ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-326 के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के काम (कुल लंबाई: 206 किमी) पर भी मुहर लगा दी गई है. बता दें कि इस प्रोजेक्ट की लागत 1,526 करोड़ रुपए बताई जा रही है जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

साल 2025 के आखिरी दिन केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में देश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने वाले दो अहम हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों परियोजनाओं की कुल लागत करीब 21 हजार करोड़ रुपये है. इन प्रोजेक्ट्स से महाराष्ट्र और ओडिशा में सड़क संपर्क, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

हाईवे पर आधुनिक सुविधाएं

इस 6 लेन हाईवे पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का खास ध्यान रखा जाएगा. परियोजना के तहत 27 बड़े पुल, 164 छोटे पुल, 5.6 किलोमीटर लंबा वायडक्ट, 5 रेल ओवर ब्रिज, 10 इंटरचेंज, 17 एंट्री-एग्जिट प्वाइंट और 14 रेस्ट एरिया बनाए जाएंगे. इससे न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों और मालवाहक वाहनों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

महाराष्ट्र में 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे - पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में नासिक से सोलापुर कॉरिडोर पर बनने वाला 6 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे है. इसकी कुल लंबाई 374 किलोमीटर होगी और इस पर लगभग 19,142 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह पूरी तरह नया हाईवे होगा, जिसे आधुनिक डिजाइन और हाई-स्पीड ट्रैफिक को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा. यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सूरतङ्कचेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर का हिस्सा है और साथ ही दिल्ली से चेन्नई को जोडने वाले बड़े राष्ट्रीय हाईवे नेटवर्क में भी इसकी अहम भूमिका होगी. सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिए दो साल की समयसीमा तय की है.

यात्रा समय और रफ्तार में बड़ा सुधार

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, इस हाईवे के बन जाने से नासिक और सोलापुर के बीच की दूरी 432 किलोमीटर से घटकर 374 किलोमीटर रह जाएगी. इसके साथ ही औसत यात्रा गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकेगी. इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी.

ओडिशा में एनएच-326 का विस्तार

दूसरा प्रोजेक्ट ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 326 को चौड़ा करने और अपग्रेड करने से जुड़ा है. इस 206 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट पर करीब 1,526 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके जरिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आदिवासी व पिछड़े इलाकों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोडने में मदद मिलेगी.

अयोध्या के शौर्य, वैभव व पराक्रम के आगे नहीं टिक पाया कोई दुश्मन : सीएम योगी

अयोध्या।

श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 'प्रतिष्ठा द्वादशी' बुधवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। सीएम योगी ने अंग्रेजी नववर्ष 2026 की शुभकामना देते हुए प्रार्थना की कि यह वर्ष सभी के लिए मंगलकारी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या ने स्वतंत्र भारत में रामजन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव देखे हैं। अयोध्या के नाम से ही अहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ। कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य, वैभव व पराक्रम के आगे टिक नहीं पाया, लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ, मजहबी जुनून व सत्ता के तुष्टिकरण की निकृष्टता में पड़कर अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का अड्डा बना दिया था। सीएम योगी ने पिछली सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होता था, उस अयोध्या में पिछली सरकारों के शासन में आतंकी हमले होते थे। अयोध्या को लहुलूहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन जहां प्रभु की कृपा बरसती हो और जहां हनुमानगढ़ी में स्वयं हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, वहां कोई आतंकी कैसे घुस जाता।

राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के विरुद्ध सैन्य पराक्रम का किया शंखनाद

संवाददाता

अयोध्या.साल 2025 के अंतिम दिन धर्मनगरी अयोध्या एक ऐतिहासिक और गौरवशाली पल की साक्षी बनी जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु श्रीरामलला के प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह के द्वितीय वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने पहुंचे। इस पावन अवसर पर समूची अयोध्या राममय नजर आई और उत्सव का माहौल ऐसा था मानो त्रेतायुग जीवंत हो उठा हो। रक्षा मंत्री ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और फिर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के चरणों में शीश नवाया।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा

की स्थापना रही, जिसे रक्षा मंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न किया। इस गरिमामयी उपस्थिति ने न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया, बल्कि रक्षा मंत्री के संबोधन ने देश की सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर एक कड़ा संदेश भी वैश्विक पटल पर प्रस्तुत किया। राजनाथ सिंह ने अपने उद्बोधन की शुरुआत अत्यंत भावुक होकर ÷नाथ आजु मैं कहा न पावा÷ की चौपाई से की और कहा कि आज उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे जीवन की समस्त उपलब्धियां उन्हें प्राप्त हो गई हों। उन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर के लिए स्वयं को राघवेंद्र सरकार द्वारा चुना हुआ बताते हुए इसे अपने जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन करार दिया। रक्षा मंत्री ने दो वर्ष पूर्व हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को स्मरण करते हुए कहा कि वह क्षण केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं था, बल्कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति की पुनर्प्रतिष्ठा थी। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या की हर गली, हर चौराहा और सरयू का हर घाट राम की कीर्ति से विभूषित है। यह आभा केवल अवध तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष आज राम के आदर्शों में डूबा हुआ है। उन्होंने उन पीढ़ियों के बलिदान को याद किया जिन्होंने 500 वर्षों तक असहनीय अपमान और संघर्ष सहा लेकिन अपनी आस्था को कभी डिगने नहीं दिया। राम मंदिर आंदोलन को दुनिया का सबसे बड़ा और ग्रैंड नैरेटिव बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यह भूगोल और समय की सीमाओं से परे एक ऐसा अहिंसक संघर्ष था, जिसका उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं और नहीं मिलता।

झारखंड : हजारीबाग में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, ईसाई धर्म अपनाने वालों को 15 हजार का प्रलोभन, 8 गिरफ्तार

हजारीबाग. संवाददाता।

झारखंड के हजारीबाग जिले के विभिन्न प्रखंडों में बड़े पैमाने पर मतांतरण का खेल चल रहा है. अब इसकी पहुंच हजारीबाग शहर में भी हो गई है. ताजा मामला सदर प्रखंड के मंडई से जुड़ा है, जहां कोर्रा थाना अंतर्गत महेंद्र कालोनी के एक बंद घर में मतांतरण का खेल चल रहा था. मामले का खुलासा तब हुआ जब यहां चल रहे चंगाई सभा में एक युवक ने मतांतरण से इंकार कर दिया. इसके बाद युवक के साथ मारपीट की गई. किसी तरह युवक ने भाग कर इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी. इसके बाद मंडई में हंगामा मच गया. ग्रामीणों ने मतांतरण कराने आए लोगों को पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जयशंकर ने बांग्लादेश में पाकिस्तान नेशनल स्पीकर नेता से मिलाया हाथ

ढाका : एजेंसी।

विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदना प्रकट की। जयशंकर ने तारिक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक निजी पत्र भी सौंपा। हालांकि, इस दौरान जयशंकर ने वहां मौजूद पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनेता से हाथ भी मिलाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के वरिष्ठ नेताओं की पहली मुलाकात भी माना जा रहा है। जयशंकर ने बांग्लादेश दौरे पर जिस पाकिस्तानी राजनेता से हाथ मिलाया, उनका नाम सरदार अयाज सादिक है। वह पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं। यह एक अनौपचारिक मुलाकात थी, जो वहां मौजूद नेताओं के बीच हुई। इस दौरान दोनों नेताओं में आपसी संबंधों को लेकर किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई। यही कारण है कि इस मुलाकात की तस्वीर न तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने पोस्ट की और ना ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने।

चुनाव | खालिदा जिया के बेटे को सौंपी चिट्ठी

पीएम मोदी का संदेश लेकर ढाका पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर

ढाका एजेंसी ।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज नेता बेगम खालिदा जिया के निधन पर भारत ने गहरा दुख व्यक्त किया है। इस दुख की घड़ी में भारत की संवेदनाएं प्रकट करने के लिए विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर बुधवार को विशेष विमान से ढाका पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजा गया शोक संदेश और भारत सरकार व भारतीय जनता की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की।

पीएम मोदी का संदेश लेकर पहुंचे जयशंकर - विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे ढाका एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने उनका स्वागत किया। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि एस. जयशंकर ने पीएम मोदी का शोक संदेश खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को दिया। उन्होंने संदेश दिया कि भारत इस कठिन समय में बांग्लादेश के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। जयशंकर ने खालिदा जिया के लंबे राजनीतिक जीवन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में उनके योगदान को सम्मानपूर्वक याद किया।

गौरतलब है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन और तीन बार देश की प्रधानमंत्री रहीं बेगम खालिदा जिया का मंगलवार को ढाका में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वह 80 वर्ष की थीं। उनके निधन की खबर से बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है।

विराट हिंदू सम्मेलन में मोहन भागवत बोले- अलगाव और भेदभाव को मन से निकालो

लोकशक्ति

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत रायपुर दौरे पर हैं। आज अभनपुर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने समाज और राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर पांच प्रमुख बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संकटों पर केवल चर्चा से समाधान नहीं निकलता, बल्कि उपायों पर गंभीर मंथन आवश्यक है। उपाय हमारे पास ही मौजूद हैं, जरूरत है उन्हें अपनाने की। हिंदू सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, भाजपा नेता धरमलाल कौशिक सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जीवन में कुछ मूल्यों को आत्मसात करना जरूरी है। पहली बात, अपनी दृष्टि से अलगाव और भेदभाव को निकालना होगा। सभी को अपना मानकर व्यवहार करें। हम पूरे हिंदू समाज को एक मानते हैं, लेकिन दुनिया हिंदुओं में भेद देखती है। जाति, पंथ और भाषा का फर्क किए बिना सबको अपना मित्र बनाना चाहिए। सभी भारतवासी हैं और पूरा भारत हमारा है। प्रत्येक व्यक्ति में राम विराजमान हैं। सभी व्यवस्थाएं सभी हिंदुओं के लिए खुली होनी चाहिए।

दूसरी बात, जब व्यक्ति अकेला पड़ जाता है तो वह नशे जैसी बुराइयों में उलझ जाता है। आपसी संवाद और मित्रों के साथ बातचीत से इससे बचा जा सकता है। आज घरों में भी बातचीत कम हो गई है। इसलिए सप्ताह में एक दिन पूरा परिवार साथ बैठे, भजन करे, मां के हाथ का बना भोजन करे और तीन-चार घंटे आपसी गपशप करे। पूर्वजों की सीख आज के समय में कितनी प्रासंगिक है, इस पर चर्चा हो। आदेश देने के बजाय संवाद से सहमति बनाकर उसे घर में लागू करें।

तीसरी बात, हम अपने और परिवार के लिए समय व धन खर्च करते हैं, लेकिन देश के लिए कितना करते हैं, इस पर विचार जरूरी है। देश सुरक्षित रहेगा तभी हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहेंगे। हिंदुत्व की रक्षा के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, वे हमारे आदर्श हैं। इस विषय पर भी घर में साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए। कुटुंब प्रबोधन और मंगल संवाद पर ध्यान देना आवश्यक है।

पर्यावरण पर जताई चिंता

मोहन भागवत ने पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऋतु चक्र बदल रहा है। जंगल कम होने से पानी की समस्या बढ़ रही है। इसलिए अपने घर से ही पानी बचाने की शुरुआत करें। नल टपक रहा हो तो तुरंत ठीक कराएं। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। पेड़ लगाएं। घर के आंगन या छत पर सब्जियां उगाने का प्रयास करें और अपने आसपास हरियाली बढ़ाएं।

बांग्लादेशी नागरिकों को बार्डर पर भेजा गया, गुजरात के रास्ते जबलपुर आए थे, दो साल जेल काटने के बाद रिहा हुए

संवाददाता। एमपी के जबलपुर में वर्ष 2023 में गुजरात के रास्ते आई महिला व पुरुष दो सजा जेल में काटने के बाद बार्डर पर भेज दिया गया है. वे गुजरात के रास्ते से जबलपुर में पहुंचे थे. यहां पर दोनों दिन में भीख मांगते और रात को गोरखपुर स्थित मैदान में रहते थे. संदिग्ध गतिविधियों के चलते जब पुलिस की नजर उन पर पड़ी और पूछताछ की गई, तो वे अपनी पहचान से संबंधित कोई जानकारी नहीं दे सके. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मीनारा बेगम और मोहम्मद मोसूर बांग्लादेश से मार्च-अप्रैल 2023 में बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल होते हुए गुजरात के रास्ते मध्यप्रदेश के जबलपुर पहुंचे थे. यहां आकर उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया. वे दिन में भीख मांगते और रात को गोरखपुर स्थित मैदान में रहते थे. मुखबिर से सूचना मिलने पर दोनों से

नागरिकता से संबंधित कागजात मांगे गए तो नहीं दे पाए. दोनों की भाषा भी अलग थी. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे मूल रूप से बांग्लादेश के निवासी हैं और भारत में रहने के लिए उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है. इसके बाद गोरखपुर थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 14ए के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया. निचली अदालत ने दोनों आरोपियों को चार-चार साल की सजा सुनाई थी।

प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि यंत्रों से हो रहे हैं समृद्ध, बीज निगम द्वारा किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे आधुनिक कृषि यंत्र

इस वित्तीय वर्ष में अब तक 882 किसानों को मिला आधुनिक कृषि यंत्र

किसान विकसित भारत विजन की परिकल्पना की ओर हो रहे अग्रसर

रायपुर । प्रदेश के किसान खेती-किसानी में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। वहीं विकसित भारत विजन की परिकल्पना की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किसानों को अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका बड़ी संख्या में किसान लाभ ले रहे हैं। किसान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर खेती किसानी के उन्नत एवं आधुनिक तौर तरीके अपना रहे हैं, जिससे किसानों को पारंपरागत किसानी से अधिक फायदा हो रहा है।

शासकीय अनुदान पर आधुनिक एवं उन्नत कृषि यंत्र किसानों को

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन द्वारा कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की

योजनाएं संचालित हैं जिनसे किसान लगातार लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे वो उन्नत बीज हो या अन्य विभागीय योजनाएं। इसी क्रम में बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किसानों के हित में शासकीय अनुदान पर आधुनिक एवं उन्नत किस्म में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों को किसानों को उपलब्ध कराया जाता है द्य खेती किसानी के विभिन्न चरणों जुताई, बुआई, रोपाई, फसल कटाई जैसे सभी चरणों के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र किसान के द्वारा चयन आधार पर उपलब्ध कराया जाता है, इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। बीज निगम द्वारा किसानों को शक्ति चलित कृषि यंत्र जैसे - रोटावेटर, स्व चलित रीपर, पैडी ट्रांसप्लांटर, लेज़र लैंड लेवलर, पावर वीडर, मल्चर, थ्रेशर, सीड ड्रिल, सहित अन्य आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।इन कृषि यंत्रों के उपयोग से किसानों को समय की बचत के साथ-साथ श्रम लागत में भी कमी हो रही है। किसानों का कहना है कि आधुनिक यंत्रों के प्रयोग से खेती का कार्य कम समय में और अधिक सटीक तरीके से हो पा रहा है, जिससे फसल की गुणवत्ता बेहतर हुई है। परिणाम स्वरूप बाजार में उन्हें उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है।

882 किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्रों से किया गया लाभान्वित

बता दें कि बीज निगम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। निगम द्वारा किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने की योजना क्रियान्वित है। जिससे कृषि क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

वर्ष 2025-26 में अभी तक 882 किसान को अनुदान पर कृषि यंत्रों से लाभान्वित हो चुके हैं।

स्व-चलित रीपर से कटाई हुई आसान

बिलासपुर जिले के किसान नारायण दल्लू पटेल ने बीज निगम के माध्यम से अनुदान पर स्व-चलित रीपर प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि पहले एक एकड़ फसल की कटाई में 10-12 मजदूर और पूरा दिन लगता था, जबकि अब वही कार्य 2-3 घंटे में पूरा हो जाता है। इससे कटाई लागत में 50-60 प्रतिशत तक कमी आई है और समय पर कटाई संभव हो सकी है।रायपुर जिले के किसान हीरालाल साहू ने बताया कि रोटावेटर के उपयोग से खेत की जुताई एक ही बार में हो जाती है। पहले जहाँ खेत तैयार करने में 3-4 दिन लगते थे, अब कुछ घंटों में कार्य पूर्ण हो जाता है। इससे फसल उत्पादन में 20-25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।सीड ड्रिल से बीज की बचत और बेहतर उत्पादनखैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के किसान लेखूराम छेदईया ने अनुदान पर सीड ड्रिल मशीन क्रय किए है। उन्होंने बताया कि इस मशीन का प्रयोग बोआई में करने पर बीज की 15-25 प्रतिशत तक बचत होती है। समान दूरी और गहराई पर बोआई से अंकुरण बेहतर हुआ है और उत्पादन में 20-30 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने ली मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक, दावा-आपत्ति के संबंध में दी गई जानकारी

रायगढ़।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 15-लैलूंगा, 16-रायगढ़, 18-खरसिया एवं 19-धरमजयगढ़ द्वारा अपने-अपने अनुविभाग क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित कर प्रारुप 9, 10, 11, 11-ए एवं 11-बी की सूची उपलब्ध कराई गई और 23 से 29 दिसम्बर 2025 तक प्राप्त दावा/आपत्ति की जानकारी दी गई। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम अन्तर्गत रायगढ़ जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र 15-लैलूंगा, 16-रायगढ़, 18-खरसिया एवं 19-धरमजयगढ़ के सभी 1217 मतदान केन्द्रों/विहित स्थानों में एवं सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सर्व तहसीलदार/सह सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 23 दिसम्बर 2025 किया गया है। सभी मतदाता अपना नाम की जांच अपने मतदान केन्द्रों अथवा सीईओ छत्तीसगढ़ के वेबसाइड में कर सकते है।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे सभी नवीन मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गया है या 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष होगा या फिर जिनका नाम किसी कारण से छूट गया है, ऐसे मतदाता अपने मतदान केन्द्र में जाकर फार्म-6 एवं घोषणा पत्र भरकर अपना नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु बीएलओ अविहित अधिकारी के पास या निर्वाचन आयोग के वेबसाइड httpsÑ//voters-eci.gov.in में ऑनलाईन आवेदन 22 जनवरी 2026 कर सकते है। उपरोक्त कार्य हेतु सभी मतदान केन्द्रों में अविहित अधिकारी एवं बीएलओ द्वारा शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में दावा/आपत्ति संबंधी फार्म प्राप्त किये जायेंगे।

ऐसे मतदाता जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज है और जिन्हें निवास स्थान परिवर्तन या प्रविष्टियों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो या दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हाकिंत किया जाना हो तो वे फार्म-8 एवं घोषणा पत्र भरकर बीएलओ अविहित अधिकारी के पास मतदान केन्द्र में जमा कर सकते है। 14 फरवरी 2026 तक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने-अपने कार्यालयों मे प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण एवं सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ में स्थापित हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। जिसके टोल फ्री नंबर 1950 या दूरभाष नंबर 07762-222290 एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित हेल्प डेस्क में सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते है।

खुले आसमान के नीचे कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने जनदर्शन में सुनीं फरियादियों की समस्याएँ

मीठी धूप में आवेदकों ने प्रशासन की इस पहल को सराहा

कोरिया। कोरिया जिले की कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने वर्ष 2025 के अंतिम साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट परिसर के खुले आसमान के नीचे, मीठी धूप में आमजन की समस्याएँ सुनीं। बैकुंठपुर, पटना, सोनहत एवं पोड़ी-बचरा से आए फरियादियों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए, जिन्हें कलेक्टर ने गंभीरता से पढ़ते हुए त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उल्लेखनीय है कि आज वर्ष 2025 का अंतिम जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने आम नागरिकों की समस्याएँ न केवल सुनीं, बल्कि उनके शीघ्र एवं नियमसम्मत समाधान के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। कलेक्टर त्रिपाठी ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल आवेदनों को प्राप्त करना नहीं, बल्कि उनका समयबद्ध और नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड के बीच आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस उद्देश्य से खुले आसमान के नीचे धूप में जनदर्शन आयोजित किया गया। जनदर्शन कार्यक्रम में भूमि पर अवैध कब्जा हटाने, बंटांकन, नामांतरण, नक्शा प्रदान करने, लंबित राशि के भुगतान सहित विभिन्न विषयों से संबंधित 40 आवेदन प्राप्त हुए। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर सुरेंद्र वैध सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती हेतु आवेदन 12 जनवरी तक

कोरिया । महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों बाल देखरेख संस्थाओं के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए राज्य स्तर से विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पात्र आवेदकों से 12 जनवरी 2026 तक आवेदन आमंत्रित्र किया गया है। बाल देखरेख संस्था अंतर्गत बाल गृह (बालक) में परामर्शदाता-1 (अ.ज.जा.), परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर-1 पद (अ.ज.जा.), हाउस फादर-2 पद (अ.ज.जा.), पैरामेडिकल स्टॉफ-1 पद (अ. ज.जा.), स्टोर कीपर सह लेखापाल-1 पद (अ.ज.जा.), एजुकेटर 1 पद (अ.ज.जा.), आर्ट एवं काफ्ट सह संगीत शिक्षक-1 पद (अ.ज.जा.), पीटी अनुदेशक सह योग शिक्षक-1 पद (अ.ज.जा.), रसोईया-2 पद (अना-1,अ.ज.जा.-1), सहायक सह चौकीदार-2 पद (अना-1,अ.ज.जा.-1), हाउस कीपर-1 पद (अ.ज.जा.) तथा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण में सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रारंभिक बाल्यावस्था एजुकेटर-1 पद (अना.) की भर्ती की जानी है। उक्त पदों के लिए आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग (कलेक्टर कार्यालय के पीछे छिंदडांड) को प्रेषित करना होगा। आवेदन हेतु वर्गवार पदपूर्ति किये जाने वाले पदों का विस्तृत विवरण पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव, अन्य अहर्ताओं, संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण, आवेदन पत्र एवं पत्राचार का पता महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एव वेबसाईट www.cgstate.gov.in तथा www.cgwcd.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

रानीतराई साप्ताहिक बाजार में नकली नोट चलाने वाले पतिङ्कपत्नी गिरफ्तार, 1.70 लाख रुपये के नकली नोट जब्त

दुर्ग। थाना रानीतराई क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार में नकली नोट चलाने का मामला सामने आने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अरूण कुमार तुरंग एवं उसकी पत्नी राखी तुरंग को हिरासत में लिया है। आरोपियों के कब्जे से 500, 200 एवं 100 रुपये के कुल 1,70,500 रुपये के नकली नोट, कलर फोटो कॉपी प्रिंटर एवं पेपर बरामद किए गए हैं।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 29 दिसंबर 2025 को रानीतराई साप्ताहिक बाजार में नकली नोट चलने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। जांच के दौरान प्रार्थी तुलेश्वर सोनकर (40 वर्ष), निवासी ग्राम सिलपट, थाना भखारा, जिला धमतरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी पत्नी के साथ रानीतराई बाजार में सब्जी बेचने आया था। शाम लगभग 5.30 बजे एक पुरुष एवं महिला ने 60 रुपये की सब्जी खरीदी और 500 रुपये का नोट दिया। बाद में बाजार में नकली नोट चलने की जानकारी मिलने पर जब उसने अपने गल्ले की जांच की, तो नोट नकली प्रतीत हुआ।

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने रानीतराई बाजार के कई अन्य व्यापारियों से भी सामान खरीदकर नकली नोट चलाए थे। इसके आधार पर थाना रानीतराई में अपराध क्रमांक 123/2025 धारा 178, 179, 180, 181 एवं 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। पूछताछ में आरोपी अरूण कुमार तुरंग ने नकली नोट छापकर बाजार में चलाने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि ऑनलाइन कलर फोटो कॉपी प्रिंटर एवं पेपर मंगाकर 500 रुपये के नोट की फोटो कॉपी कर नकली नोट छापे गए, जिन्हें पाटन साप्ताहिक बाजार तथा रानीतराई बाजार में चलाया गया। आरोपी रानीतराई बाजार में 5,200 रुपये के नकली नोट लेकर गया था। इसके बाद आरोपियों के निवास ग्राम सोनपैरी, मुजगहन, जिला रायपुर में विधिवत तलाशी ली गई।

रामलला दर्शन योजना : रायगढ़ जिले के 1200 से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या धाम में किए प्रभु श्रीराम के दर्शन

रायगढ़ । छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से अब तक 1200 से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचकर प्रभु श्रीरामलला के पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप प्रारंभ की गई यह योजना अयोध्या धाम से लौटे श्रद्धालुओं के चेहरों पर झलकती प्रसन्नता, संतोष और भक्ति की मुस्कान इसकी सफलता का सशक्त प्रमाण है।

छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल केवल एक धार्मिक यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आस्था, संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव से परिपूर्ण एक अविस्मरणीय अनुभव बन चुकी है। छत्तीसगढ़ का भगवान श्रीराम से गहरा आत्मीय और ऐतिहासिक संबंध रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेतायुग में भगवान श्रीराम ने अपने वनवास काल का महत्वपूर्ण समय छत्तीसगढ़ की पावन भूमि

पर व्यतीत किया था। माता कौशल्या का मायका भी छत्तीसगढ़ में स्थित होने के कारण यहां के लोग भगवान श्रीराम को स्नेहपूर्वक भांजा राम कहकर संबोधित करते हैं। इसी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंध को साकार रूप देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई है।

योजना का लाभ प्राप्त करने वाले पुसौर निवासी खगेश्वर पटेल ने बताया कि कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित इस योजना ने उनके जीवन का सपना साकार कर दिया। श्रीमती राजकुमारी साव ने यात्रा को सहज, सुरक्षित और अत्यंत सुखद बताते हुए कहा कि शासन-प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि पूरा समूह एक परिवार की भांति यात्रा कर सका। उमेश सिंह सिदार ने भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान रखा गया। वहीं श्रीमती सावित्री भगत ने कहा कि अयोध्या में रामलला के दर्शन उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सभी श्रद्धालुओं ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। बता दें कि रामलला दर्शन योजना अंतर्गत राज्य के पात्र श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम स्थित भगवान श्रीरामलला के दर्शन हेतु पूर्णतः निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं को छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक निःशुल्क आवागमन की सुविधा प्रदान की जाती है। यात्रा अवधि के दौरान ठहरने, भोजन एवं नाश्ते की संपूर्ण व्यवस्था शासन द्वारा सुनिश्चित की जाती है। यात्रियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक चिकित्सा एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की भी समुचित व्यवस्था की जाती है।

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने घोराघाटी लातनाला डायवर्सन डेम का किया निरीक्षण

डेम के कटाव का स्टीमेट बनाकर प्रस्ताव भेजने कलेक्टर ने एसडीओ को दिए निर्देश

सेमरापाली में लातनाला के ढलान में स्टापडेम बनाने के निर्देश

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने सारंगढ़ से 14 किमी दूर ग्राम घोराघाटी में वर्ष 2008 में लात नाला पर करीब 8 करोड़ की लागत से बने लात नाला डायवर्सन परियोजना का निरीक्षण किया। इस डैम का निर्माण 2011-12 में पूरा हुआ था। घोराघाटी डेम के कटाव का स्टीमेट बनाकर प्रस्ताव भेजने और सेमरापाली में लातनाला के ढलान में जल संसाधन विभाग से स्टापडेम बनाने कलेक्टर ने एसडीओ जल संसाधन को निर्देश दिए। इसी प्रकार पंचायत एवं ग्रामीण विभाग से भी तटबंध बनाने कलेक्टर ने सीईओ इंद्रजीत बर्मन को निर्देश दिए। इस दौरे में सरपंच संतोष चौहान, ग्रामीण सहित सीईओ जनपद पंचायत राधेश्याम नायक, इंजीनियर आदि उपस्थित थे।

प्लेसमेंट कैम्प में 52 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

रायगढ़, । जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायगढ़ द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प में जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि प्लेसमेंट कैम्प में 3 नियोजक संस्थानों द्वारा कुल 288 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। कैम्प में 123 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए पंजीकृत हुए, जिनमें से 52 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है, जबकि शेष अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

प्लेसमेंट कैम्प के अंतर्गत फील्ड टेक्नीशियन, एसेट मैनेजर, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड एवं वेटर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया सम्पन्न हुई। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित यह प्लेसमेंट कैम्प युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध हुआ है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल आकस्मिक सिरपुर पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा

महासमुंद । महासमुंद जिले के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल सिरपुर में आगामी 01 जनवरी को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत एवं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज सिरपुर पहुंचकर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया और तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह मौजूद थे।

निरीक्षण के दौरान पर्यटन मंत्री अग्रवाल ने लक्ष्मण मंदिर, बौद्ध विहार परिसर, उत्खनन स्थलों सहित अन्य प्रमुख पुरातत्व स्थलों का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्थलों की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, मार्ग व्यवस्था, सूचना पट्टिकाओं तथा पर्यटकों की सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए। साथ ही, ऐतिहासिक धरोहरों की संरक्षण संबंधी आवश्यक तैयारियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान अग्रवाल ने कहा कि सिरपुर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित निरीक्षण से सिरपुर के विकास और संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग, जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम सफल और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। इस अवसर पर सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी एवं विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने सिरपुर के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी देते हुए क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले में पर्यटन विकास को लेकर चल रही योजनाओं एवं प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुरातत्व, पर्यटन विभाग के अधिकारी, संस्कृति विभाग के अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्व. अटल का जीवन हमें सिखाता है कि राजनीति सत्ता का नहीं, साधना का मार्ग है : भावना बोहरा

कवर्धा। भारतीय जनता पार्टी केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व.अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर अटल स्मृति सम्मलेन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पंडरिया विधानसभा अंतर्गत यज्ञ स्थल, कुण्डा में विधानसभा स्तरीय अटल समिति सम्मलेन का आयोजन किया गया। आयोजन में राजनांदगांव सांसद संतोष पाण्डेय, विधायक भावना बोहरा, जिला भाजपा अध्यक्ष राजेन्द्र चंद्रवंशी , कबीरधाम जिला संगठन प्रभारी महेश वर्मा ने स्व.अटल के छायाचित्र में पुष्पांजलि अर्पित कर सम्मलेन का शुभारम्भ किया।इस अवसर पर राजनांदगांव सांसद संतोष पाण्डेय ने संबोधित करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, बल्कि विदेश मंत्री और संसद की विभिन्न महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विपक्ष के एक सक्रिय नेता भी रहे। छत्तीसगढ़वासियों की आकाँक्षाओं को उन्होंने पूरा करते हुए इसे अलग राज्य बनाया और आज हमारा प्रदेश निरंतर विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है।

भटगांव विधानसभा: 150.56 करोड़ की लागत से बनेंगी 33 नई सड़कें, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से मिली स्वीकृति

सूरजपुर। भटगांव विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के सतत प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए क्षेत्र में 150.56 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस स्वीकृति से भैयाथान और ओड़गी ब्लॉक के ग्रामीण अंचलों में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। 33 प्रमुख मार्गों का होगा निर्माण और उन्नयन विभाग द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार, कुल 33 सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसमें ओड़गी और भैयाथान ब्लॉक के कई ऐसे मार्ग शामिल हैं, जिनकी मांग लंबे समय से क्षेत्रवासी कर रहे थे। इन सड़कों के बनने से सुदूर वनांचल क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मुख्य मार्गों से हो जाएगी।

प्रमुख स्वीकृत कार्य:

स्वीकृत कार्यों में 28.99 करोड़ की लागत से बनने वाली ओड़गी नवाटोला रोड (8.20 किमी से धुईडीह पंडोपारा) सबसे प्रमुख है। इसके अलावाः

भवरखोह से जमड़ी (लागतः 9.50 करोड़)

खोंड नवापारा से केसर (लागतः 8.73 करोड़)

माड़र से भाड़ी नवापारा (लागतः 8.38 करोड़)

भैयाथान ब्लॉक में भौराही देवालय से शिवपुर मार्ग

''जनता की सुविधा पहली प्राथमिकता'' मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा, क्षेत्र का विकास और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। 150.56 करोड़ की राशि से स्वीकृत ये सड़कें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देंगी। किसानों, छात्रों और आम नागरिकों को आवागमन में हो रही परेशानियों से निजात मिलेगी। हम गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में 175 अटल परिसर की स्थापना की गई - राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा है कि भाजपा का छत्तीसगढ़ संगठन बहुत प्रभावी और मजबूत है। केन्द्रीय स्तर पर जब भी हम संगठनात्मक गतिविधियों की राज्यवार समीक्षा करते हैं, तब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक इकाइयाँ पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सबसे अग्रणी प्रदेशों में गिनी जाती हैं। श्री सिंह ने अटल जी की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के इस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनन्दन करते हुए कहा कि अटल जन्म शताब्दी वर्ष में छत्तीसगढ़ अकेला एक ऐसा प्रदेश रहा, जहाँ 175 अटल परिसर की स्थापना की गई। हर सकारात्मक काम का कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष विरोध करता ही है भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री सिंह अटल जन्म शताब्दी कार्यक्रम की समीक्षा बैठक और कार्यकर्ता सम्मेलन व सम्मान समारोह के निमित्त बुधवार को राजधानी के प्रवास पर रहे। इस दौरान कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि संसद सत्र अभी सम्पन्न हुआ है, हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। कई विधेयकों पर चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष ढंग से अपनी बात भी नहीं रख पाया। उसके बाद बाहर आकर उन पर भ्रम फैलाने में लगा है। 'वीबी जी राम जी' में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है अर्थात इससे लोगों को 25 दिन अधिक रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही जो योजनाएँ बनेंगीं, जो काम होगा, वह ग्राम की आवश्यकता के अनुरूप ग्रामसभा और ग्राम पंचायत तय करेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी को एक पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया है। लेकिन, विपक्ष इसमें भी भ्रम फैला रहा है कि यह सब केन्द्र सरकार तय करेगी। हर सकारात्मक काम का कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष विरोध करता ही है। श्री सिंह ने कहा कि देशभर के अनेक स्थानों से मिली शिकायतों के बाद मनरेगा के तहत कई विधानसभाओं में जो गड्ढे-ही-गड्ढे दिखते थे और जिन पर काम ही नहीं हुआ, उनका वित्तीय आवंटन रोक दिया गया। अब इस योजना में बायोमेट्रिक्स के उपयोग को बढ़ावा देने, उसके कम्प्यूटरीकरण करने पर जोर दिया गया है। इससे विकास और बुनियादी जरूरतों के काम भी होंगे, ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा और गाँव वाले खुशहाल भी होंगे। बंगाल में सरकार के संरक्षण में ऑर्गेनाइज्ड करप्शन हुआ है भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री सिंह ने दावा किया कि प.बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। बंगाल में सरकार के संरक्षण में ऑर्गेनाइज्ड करप्शन हुआ है। योजनाओं में कहीं-न-कहीं लीकेज होता है। सरकार उस पर कार्रवाई करती है लेकिन सरकार के संरक्षण में ही अगर बड़े लेवल की करप्शन हो, लूट मची हो तो वह चिंताजनक है। प.बंगाल में हमारी पहले तीन सीटें आई थी, बाद में हम 77 सीटें जीते। इस बार बंगाल में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ भाजपा की सरकार बनेगी क्योंकि टीएमसी के शासन में हिंसा, करप्शन से वहां की जनता परेशान है, त्रस्त है। बंगाल जैसी हिंसा पूरे देश में कहीं नहीं है, बंगाल जैसा करप्शन पूरे देशभर में कहीं नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी की शुरू से कार्ययोजना और सोच रही है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण के मार्ग में चले। एक वर्ग को खुश करने के लिए बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है फिर भी उसको नहीं रोक पाए, यह सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। केंद्र सरकार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत की ओर तेजी से अग्रसर है भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री सिंह ने नक्सल उन्मूलन अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि देश के लिए यह सम्मान का विषय है कि नक्सलवाद की समस्या से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रणनीतिक मार्गदर्शन और प्रदेश सरकारों के सहयोग से केंद्र सरकार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत की ओर तेजी से अग्रसर है और 31 मार्च 2026 तक पूरा देश हथियारबंद नक्सलियों से मुक्त हो जाएगा। इसमें सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह की रणनीति और प्रदेश सरकारों से श्री शाह का सतत सम्वाद जारी है। इसके साथ ही सरकार नक्सलियों से कठोरता से पेश आ रही और साथ ही उनसे विकास की मुख्यधारा में आने को भी कह रही है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की योजनाओं की लम्बी कतार लगा दी है।

बस्तर के स्कूली बच्चों को मिली बैंकिंग की बड़ी सौगात

स्कालरशिप की राशि सीधे आएगी खाते में

जगदलपुर। बस्तर जिले के हजारों स्कूली विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए नए साल से ठीक पहले एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बच्चों को मिलने वाली सरकारी छात्रवृत्ति की पूरी राशि बिना किसी बैंकिंग अड़चन या कटौती के सीधे उनके हाथों में पहुंचे। कलेक्टर हरिस एस ने जिले के लीड बैंक प्रबंधक और डाक विभाग को निर्देश जारी करते हुए आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए जीरो बैलेंस खाते खोलने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है, ताकि बैंक अब मिनिमम बैलेंस के नाम पर छात्रों के पैसों में कटौती न कर सकें।

सामान्यतः बचत खातों में न्यूनतम राशि न रखने पर बैंक पेनाल्टी काट लेते हैं। चूंकि राज्य छात्रवृत्ति के तहत मिलने वाली राशि सीमित होती है। ऐसे में मिनिमम बैलेंस की शर्तों के कारण कई बार बच्चों के खाते से पैसा कट जाता था और वे शासन की योजना के वास्तविक लाभ से वंचित रह जाते थे। इसे देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है कि कक्षा तीसरी से आठवीं तक के छात्रों के खाते अब पूर्णतः जीरो बैलेंस वाले होंगे। ये खाते न्यूनतम राशि की सीमा से मुक्त रहेंगे और किसी भी स्थिति में बंद नहीं किए जाएंगे। जिससे छात्रवृत्ति का पैसा सुरक्षित रहेगा। ?ग्रामीण अंचलों में बैंकिंग सुविधाओं की कमी को देखते हुए प्रशासन ने इस बार डाकघरों को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। सुदूर गांवों में रहने वाले बच्चों को अब खाता खुलवाने के लिए शहर के बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्य डाकघर अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि वे ग्रामीण डाकघरों और शाखाओं के माध्यम से स्कूलों व गांवों में विशेष शिविर आयोजित करें। इन शिविरों में मौके पर ही बच्चों के आधार सीडेड बैंक खाते खोले जाएंगे।

जिले में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन, अब तक 4,379 आवारा श्वानों का बंधियाकरण एवं एंटी रेबिस टीकाकरण किया गया

रायपुर । कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिले में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभावी एवं सतत क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवारा श्वानों का बंधियाकरण (नसबंदी) एवं एंटी रेबिस टीकाकरण किया जा रहा है, जिससे श्वानों की संख्या पर नियंत्रण के साथ-साथ जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आयुक्त नगर निगम विश्वदीप के मार्गदर्शन में नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से घुमन्तु श्वानों को निगम के डॉग कैचर दल द्वारा पकड़कर नगर निगम के एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, बैरनबाजार लाया जाता है। यहां प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा श्वानों की नसबंदी के साथ-साथ एंटी रेबिस का टीकाकरण किया जा रहा है। इस विशेष कार्य के लिए दो चिकित्सकों की तैनाती की गई है। नसबंदी उपरांत 3 से 4 दिवस तक पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद श्वानों को उसी स्थान पर सुरक्षित रूप से छोड़ा जाता है, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। इसी क्रम में नगर निगम बिरगांव में भी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिसके पूर्ण होने के पश्चात् क्षेत्र में पशु जन्म नियंत्रण कार्य को और अधिक गति मिलेगी। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सा सेवाएं के संयुक्त संचालक डॉ. शंकर लाल उइके के मार्गदर्शन में शासकीय पशु चिकित्सालय बैरनबाजार एवं भांठागांव में विभिन्न पशु प्रेमियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से श्वानों की नसबंदी एवं एंटी रेबिस टीकाकरण किया जा रहा है। पशु प्रेमियों द्वारा श्वानों को इन चिकित्सालयों में लाकर नसबंदी कराई जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल माह से अब तक जिले में कुल 4379 श्वानों की नसबंदी की जा चुकी है। इनमें नगर निगम के एबीसी सेंटर द्वारा 3604 तथा शासकीय पशु चिकित्सालयों द्वारा 775 श्वानों की नसबंदी की गई है। इस पहल से श्वानों की जन्म दर में अपेक्षित नियंत्रण देखा जा रहा है। शासन द्वारा पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आम नागरिकों की सुविधा हेतु डॉग से संबंधित सूचना अथवा शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर निदान 1100 जारी किया गया है। नागरिक इस नंबर पर संपर्क कर अपनी शिकायत अथवा सूचना दर्ज करा सकते हैं।

वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं और शतकवीरों का सम्मान अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलिः सांसद

अटल जी का छत्तीसगढ़ निर्माण और अंत्योदय का सपना आज भी हमारी प्रेरणाःसांसद बृजमोहन अग्रवाल

अटल जी के विचार और संगठन निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ा रही भाजपाः बृजमोहन

रायपुर । रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर रायपुर जिला भाजपा द्वारा एकात्म परिसर में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह तथा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने श्रद्धेय अटल जी के साथ कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नींव रखी। सम्मानित वरिष्ठजनों में सचिनानंद उपासने , सुभाष राव जी, मोहन चौपड़ा , छगन मुंदड़ा एवं श्रीचंद सुंदरानी शामिल रहे। इसके साथ ही जिला रायपुर की चारों विधानसभाओं में 100 से अधिक नए सदस्यों को भाजपा की सदस्यता दिलाने वाले शतकवीरों का भी सम्मान कर संगठन की मजबूती, विस्तार और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये सम्मान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों, संघर्षों और संगठन निर्माण के प्रति उनके समर्पण को समर्पित है, क्योंकि जिन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और शतकवीरों को आज सम्मानित किया गया है, उन्होंने अटल जी की नीतियों और आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल एक राज्य के रूप में नहीं, बल्कि सपनों, संभावनाओं और आत्मसम्मान के रूप में किया। उनका सपना था कि यह राज्य गरीब, किसान, आदिवासी और गांव के अंतिम व्यक्ति के विकास का मॉडल बने।

उन्होंने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का गठन क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, प्रशासन को जनता के नजदीक लाने और संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की ऐतिहासिक पहल थी। अटल जी की अंत्योदय सोच ने गरीबों के लिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को नीति के केंद्र में रखा। श्री अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण विकास, सड़क कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान और किसानों के हित में लिए गए निर्णय आज भी देश को दिशा दे रहे हैं। अटल जी का जीवन राष्ट्र सेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवाद की राजनीति का जीवंत उदाहरण है। अंत में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अटल जी के विचार, उनके आदर्श और उनका राष्ट्र निर्माण का संकल्प आज भी हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक है। उनके सपनों के छत्तीसगढ़ को और सशक्त, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेश मूणत, विधायक मोतीलाल साहू, सुनील सोनी, महामंत्री अमित साहू , जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर समेत भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये सम्मान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों, संघर्षों और संगठन निर्माण के प्रति उनके समर्पण को समर्पित है, क्योंकि जिन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और शतकवीरों को आज सम्मानित किया गया है।

किसान के टोकन पर व्यापारी का धान खपाने वाले को एसडीएम ने रंगे हाथों पकड़ा

जगदलपुर।

बस्तर कलेक्टर हरिस एस के निर्देश पर धान के अवैध परिवहन के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सोमवार को बकावंड के एसडीएम मनीष वर्मा ने बड़ी कार्रवाई की। सोमवार 29 दिसंबर को धान उपार्जन केंद्र करपावंड के औचक निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने व्यापारी और किसान की मिलीभगत से चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया, जिसमें किसान के टोकन पर व्यापारी का धान खपाने का प्रयास किया जा रहा था। मामले की जांच में यह खुलासा हुआ कि जिस टोकन पर धान बेचा जा रहा था, वह कृषक उपेन्द्र भारती पिता अर्जुन भारती के नाम पर था। जमीनी हकीकत यह थी कि कृषक उपेन्द्र भारती आजीविका के सिलसिले में हैदराबाद में निवासरत हैं और उनकी जमीन पर खेती उनके भाई लखीधर भारती द्वारा की जा रही थी।

राशनकार्ड में सभी सदस्यों का ई-केव्यासी कराना अनिवार्य, खाद्य विभाग की अपील

रायपुर। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी राशनकार्डधारी परिवारों के प्रत्येक सदस्य का आधार आधारित ई-केव्यासी कराना अनिवार्य किया गया है। जिन परिवारों के कुछ सदस्यों का ई-केव्यासी अब तक नहीं हुआ है, वे शीघ्र ही अपनी नजदीकी शासकीय उचित मूल्य (राशन) दुकान में जाकर ई-केव्यासी करवा लें, ताकि भविष्य में राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। खाद्य विभाग के अनुसार जिले में कुल 22,04,430 राशनकार्डधारी सदस्यों में से 18,67,768 सदस्यों का

ई-केव्यासी पूर्ण हो चुका है, जबकि अभी भी 3,36,662 सदस्यों का द्धयङ्क्ष्ट शेष है। विभाग द्वारा शेष सदस्यों से समय रहते ई-केव्यासी कराने की अपील की गई है। फिंगरप्रिंट नहीं आने पर घबराने की जरूरत नहीं कई मामलों में नागरिकों के फिंगरप्रिंट मशीन में नहीं आ पाते हैं। ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। शासन द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन अथवा अन्य वैकल्पिक सत्यापन व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए संबंधित राशन दुकान से संपर्क किया जा सकता है। राशन दुकानदारों को दिए गए निर्देश सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि जिन राशनकार्डधारी सदस्यों का ई-केव्यासी शेष है, उनकी सूची अपने पास रखें तथा इसकी जानकारी संबंधित पार्षद, सरपंच एवं सचिव को उपलब्ध कराएं। साथ ही अपने क्षेत्र में लोगों को ई-केव्यासी के लिए लगातार जागरूक करें। आम नागरिकों से अपील सभी राशनकार्डधारी परिवारों से अपील की गई है कि वे अपने परिवार के शेष सभी सदस्यों का ई-केव्यासी समय पर अवश्य करवा लें। निर्धारित समय तक ई-केव्यासी नहीं होने की स्थिति में संबंधित सदस्य का नाम अस्थायी रूप से राशनकार्ड से हटाया जा सकता है, जिससे राशन प्राप्त करने में समस्या हो सकती है। मृत अथवा विवाह के बाद अलग रहने वाले सदस्यों की जानकारी आवश्यक यदि राशनकार्ड में दर्ज कोई सदस्य मृत हो गया है अथवा विवाह के पश्चात् अलग निवास कर रहा है, तो परिवार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित राशन दुकान या स्थानीय निकाय कार्यालय (नगर पंचायत/नगर पालिका/ग्राम पंचायत) में जानकारी देकर नाम हटाने की प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए, ताकि रिकॉर्ड अद्यतन किया जा सके।

हाइवा ने बाइक सवार युवक को रौंदा,पैर हुआ चकनाचूर, हालत गंभीर

उतई। महकाखुर्द क्षेत्र में अवैध मुरुम खनन और परिवहन एक बार फिर गंभीर सड़क हादसे की वजह बन गया। अवैध रूप से मुरुम ले जा रहे तेज रफ्तार हाइवा वाहन की चपेट में आकर डुंडेरा निवासी एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक का पैर बुरी तरह कुचल गया, हालांकि गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। तेज रफ्तार हाइवा बना हादसे की वजह बाइक सवार युवक हुआ शिकार

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा महकाखुर्द के पास हुआ। बताया जा रहा है कि हाइवा वाहन अवैध रूप से मुरुम परिवहन कर रहा था और चालक तेज व लापरवाह गति से वाहन चला रहा था। इसी दौरान पल्सर बाइक से जा रहा डुंडेरा निवासी युवक हाइवा की चपेट में आ गया। युवक गंभीर रूप से घायल पैर हुआ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई हैं, खासकर उसका एक पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 5.74 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन

कवर्धा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात

कवर्धा । उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के वनांचल और ग्रामीण क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए 5 करोड़ 74 लाख 87 हजार रुपये की लागत से तीन महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों का विधिवत पूजा-अर्चना कर भूमिपूजन किया। इन सड़क निर्माण कार्यों से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने के साथ-साथ विकास को भी नई गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सर्वप्रथम मेन रोड से ग्राम कटगो तक 6.81 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस सड़क का निर्माण 3 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। सड़क के निर्माण से वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में होने वाली कठिनाइयों से निजात मिलेगी और ग्रामीणों का मुख्य मार्ग से सीधा संपर्क स्थापित होगा। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मेन रोड से खिरसाली तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया, जिसकी लागत 1 करोड़ 36 लाख 50 हजार रुपये है। वहीं मेन रोड से लाटा तक 2.80 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का भी विधिवत भूमिपूजन किया गया जिसकी लागत 1 करोड़ 02 लाख 90 हजार है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ग्राम कटगो के ग्रामवासियों को इस बड़ी सौगात के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ग्रामीण विकास को लेकर पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि ग्राम कटगो में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 263 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनका निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गांवों में अधोसंरचनात्मक विकास को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों को यह भी जानकारी दी कि आगामी नववर्ष के अवसर पर 01 जनवरी को भोरमदेव कॉरिडोर का भव्य भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि भोरमदेव कॉरिडोर के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और कवर्धा जिले को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सभी ग्रामवासियों को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, जिला पंचायत सदस्य लोकचंद साहू, राम किंकर वर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

सांसद ने सियान गुड़ी वरिष्ठजन क्रियाकलाप एवं मनोरंजन केंद्र का किया शुभारंभ

बुजुर्गों की सेवा ही सच्ची आराधना, उनके अनुभव समाज की सबसे बड़ी पूंजीः बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर । रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को राजधानी के समता कॉलोनी स्थित दिव्यांग बालिका विकास गृह परिसर में महाराष्ट्र मंडल द्वारा नवनिर्मित सियान गुड़ी-वरिष्ठजन क्रियाकलाप एवं मनोरंजन केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया। यह केंद्र वरिष्ठजनों के सम्मान, सक्रिय जीवनशैली और आत्मनिर्भरता को समर्पित एक अभिनव एवं सराहनीय पहल है। जिसके लिए महाराष्ट्र मंडल को बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि, सियान गुड़ी केंद्र में वरिष्ठजनों के लिए मनोरंजन, रचनात्मक गतिविधियाँ, संवाद, योग, मानसिक एवं शारीरिक सक्रियता के साथ-साथ उनके अनुभव और कौशल को समाज से जोड़ने की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे वे आत्मसम्मान के साथ सक्रिय जीवन जी सकें। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी हैं। उनका अनुभव, मार्गदर्शन और आशीर्वाद जीवन की अमूल्य धरोहर है। जिन घरों में बुजुर्ग होते हैं, वहाँ अलग से भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं–बुजुर्गों की सेवा ही सच्ची आराधना है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता वृद्धाश्रमों की नहीं, बल्कि डे-केयर सेंटर्स की है, जहाँ दिन में बुजुर्गों को विविध गतिविधियों से जोड़ा जाए और शाम को ससम्मान उनके घर लौटाया जाए। बुजुर्गों को सहानुभूति नहीं, सम्मानजनक सहयोग चाहिए।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

संपादकीय

भ्रष्टाचार पर वार करती मोदी सरकार

कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की 2013 की रिपोर्ट ने यूपीए के सालों में मनरेगा की असली हालत को सामने ला दिया था। इसने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को उजागर किया 4.33 लाख से ज़्यादा नकली या खराब जॉब कार्ड, बिना हिसाब-किताब के पैसे निकालने और अनियमित काम से हजारों करोड़ रुपये का नुकसान, 23 राज्यों में मजदूरी में देरी या इनकार, और भारत की आधी से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में खराब रिकॉर्ड-कीपिंग। जिन राज्यों में ग्रामीण गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा थी - बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र - उन्होंने आवंटित फंड का सिर्फ़ 20 प्रतिशत ही इस्तेमाल किया, जिससे यह साबित होता है कि यह योजना ठीक वहीं फेल हो गई जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।

नव वर्ष की शुभकामनाएं

संजीव-ठाकुर

नव वर्ष की बेला है,
हवा में हल्की-सी धूप है
और बीते दिनों की थकान
धीरे-धीरे उतर रही है।
दर्द के जो पल
किसी कोने में अटक गए थे,
मायूसी के जो क्षण
चुपचाप हमारे साथ चलते रहे
आज उनसे विदा लेने का दिन ।
कोई वायरस अब
जीवन को छल न सके,
कोई पीड़ा अचानक
दरवाज़ा खटखटाकर
अंदर न आ पाए।
ऐसा हो कि
दर्द भी रास्ता भूल जाए
और ग़म
अपने आप ही
हमारे आसपास से
थोड़ा दूर चला जाए।
अब किसी को
दर्द का एहसास न हो,
किसी की आँखों में
अनकहा डर न रुके।
खुशियाँ
बिना बताए आएँ
और रोज़मर्रा की तरह
हमारे साथ बतियाएँ।
जो गया
वह बीत गया
कुछ मीठी यादें बनकर,
कुछ सीख बनकर।
विस्मृत हुए वे पल
अब बोझ न रहें,
बल्कि
अनुभव की तरह
हमारी जेब में रहें।
अब
सुखमय, स्वस्थ पलों का
शंखनाद
धीमा, सधा हुआ,
पर भीतर तक सुनाई देने वाला।
नव नभ खुले
बिना शोर किए,
अप्रतिम नव सूरज
रोज़ की तरह नहीं
थोड़ा अलग उगे
कुछ ज्यादा उजास के साथ,
कुछ कम थकान के साथ।
नए आभामंडल का
ऐसा आग़ाज़ हो
कि जीवन
फ़िर से
विश्वास करने लगे।
छोटी-छोटी बातों में
बड़ी राहत मिले,
रोटी, रिश्ते और
रोज़गार
तीनों सुरक्षित लगें।
माँ की चिंता
थोड़ी कम हो,
बच्चों की हँसी
थोड़ी ज़्यादा देर तक ठहरे।
बुज़ुर्गों के हाथ में
लाठी नहीं,
भरोसे की छड़ी हो।
नव वर्ष
कोई चमत्कार न सही,
पर
इतना ज़रूर करे
कि हम
कल से थोड़ा बेहतर
आज बन सकें।
नव वर्ष शुभ हो
ये शुभकामनाएँ
केवल शब्द न रहें,
हमेशा
आपके साथ चलें,
आपके भीतर
धीरे-धीरे
घर बनाएं।

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िये ऑनलाईन
PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp
Modimaya_ Vaidik_Netritva
Rashtriya Ekta
DLF-Vadra-Bhrasht Tantra
Silent Assassins Jan11,1966
Accursed & Jihadi Neighbour

पारिवारिक परंपरा को बोझ नहीं, वैश्विक समाधान समझें

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

वैश्विक परिवार दिवस, शान्ति और साझेदारी का एक दिन, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी समारोह, 'शान्ति में एक दिन' से विकसित हुआ। समग्र विश्व एक वैश्विक ग्राम है और हम सभी इस बृहत-परिवार का हिस्सा हैं। भारत ने तो वसुधैव कुटुम्बकम् का उद्घोष करते हुए समूची दुनिया को एक परिवार ही माना है। वैसे भारत की परिवार परम्परा दुनिया के लिये अनुकरणीय है। हम सभी एक परिवार हैं, चाहे हमारी नागरिकता, धर्म, जाति, सीमाएं या नस्ल कुछ भी हो। समग्र मानव जाति को एक साथ आना चाहिए और प्रेम और शान्ति में विश्वास करना चाहिए और विश्व में सुख और आशा लाने हेतु इसका अभ्यास करना चाहिए। संसार संघर्षों, युद्धों, उपद्रवों, कष्ट और पीड़ा से भरा पड़ा है। यदि हम सभी एक साथ आएं और दुनिया को प्रेम और धैर्य से ठीक करें, तो हम सभी खुशी से और अपने हृदयों में आशा के साथ रह सकते हैं। वैश्विक परिवार दिवस विविधता एवं एकता और विश्व शान्ति और अहिंसा महत्त्व के बारे में जागरूकता लाता है।

इस दिवस की शुरुआत 1997 में हुई जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नव सहस्त्राब्दी के पहले दिन से विश्व के बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय दशक की शुरुआत की। लिंडा ग्रोवर ने अमेरिका में इसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे बढ़ावा देने के अन्य प्रयासों में 'वन डे इन पीस - जनवरी 1, 2000' जैसी पुस्तकें शामिल थीं। यह पुस्तक भविष्य में एक ऐसे दिन की अवधारणा पर आधारित थी जहाँ केवल शांति हो और कोई युद्ध न हो। हालांकि, यह एक नए शांतिपूर्ण विश्व की शुरुआत मात्र थी और 1999 में, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को उस वर्ष के पहले दिन को शांति निर्माण की रणनीतियों को विकसित करने के लिए समर्पित करने का निमंत्रण मिला। इस दिन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने 2001 में वैश्विक परिवार दिवस को वार्षिक आयोजन घोषित कर दिया।

प्रत्येक वर्ष परिवार की भूमिका, उसकी बदलती संरचना और सामाजिक प्रासंगिकता पर विचार करने का अवसर देने वाला वैश्विक परिवार दिवस आज के समय में केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि वह आधुनिक समाज की सबसे गहरी विडंबनाओं और चुनौतियों को उजागर करने वाला एक चिंतन-दिवस बन गया है। परिवार मानव जीवन की वह मूल इकाई है, जहाँ व्यक्ति का भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक निर्माण होता है। भारतीय संदर्भ में परिवार केवल रक्त-संबंधों का समूह नहीं रहा, बल्कि वह संस्कारों की पाठशाला, शांति, सहयोग एवं सौहार्द की प्रयोगभूमि और जीवन-मूल्यों का आधार रहा है। इसी परिवार-परंपरा ने भारत को सदियों तक सामाजिक स्थिरता, अहिंसा, सहिष्णुता और मानवीय करुणा का देश बनाए रखा। आज विडंबना यह है कि जिस भारतीय परिवार व्यवस्था को दुनिया एक आदर्श मॉडल के रूप में देख रही है, उसी भारत में वह धीरे-धीरे उपेक्षा और विस्मृति का शिकार होती जा रही है।

वैश्वीकरण, शहरीकरण, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्तावादी जीवनशैली ने परिवार को सुविधा-केंद्रित इकाई में बदल दिया है। संयुक्त परिवारों का विघटन, एकल परिवारों का बढ़ना और रिश्तों में औपचारिकता का प्रवेश इस परिवर्तन की स्पष्ट पहचान है। माता-पिता दोनों के कार्यरत होने की स्थिति में बच्चों के साथ समय बिताना एक चुनौती बन गया है। परिणामस्वरूप बचपन, जो कभी परिवार के स्नेह, संवाद और अनुभवों से संवरता था, आज स्क्रीन, अकेलेपन और भावनात्मक रिक्तता के बीच पनप रहा है। बच्चों के जीवन में माता-पिता की अनुपस्थिति केवल समय की कमी नहीं है, बल्कि वह सुरक्षा, संवाद और मार्गदर्शन की कमी भी है। परिवार का वह सहज वातावरण, जहाँ प्रश्न पूछे जा सकते थे, गलतियाँ स्वीकार की जा सकती थीं और भावनाएँ साझा की जा सकती थीं, आज धीरे-धीरे सिमटता जा रहा है। बुजुर्ग, जो कभी परिवार की धुरी हुआ करते थे, अनुभव और संस्कार के संवाहक थे, आज कई घरों में हाशिये पर खड़े दिखाई देते हैं। उनके पास समय नहीं, धैर्य नहीं और कभी-कभी सम्मान भी नहीं बचा। यह स्थिति केवल पीढ़ियों के बीच दूरी नहीं बढ़ा रही, बल्कि समाज को उसके नैतिक आधार से भी वंचित कर रही है।

दूसरी ओर, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि वैश्विक स्तर पर आज परिवार की भूमिका को नए सिरे से समझा जा रहा है। पश्चिमी देशों में, जहाँ अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने सामाजिक अकेलेपन को जन्म दिया, अब परिवार, साझेदारी और सामूहिक जीवन की पुनर्स्थापना पर गंभीर विमर्श हो रहा है। इसी क्रम में वैश्विक परिवार दिवस को केवल परिवार के रूप में नहीं, बल्कि शांति, सहयोग और साझेदारी के प्रतीक के रूप में भी देखा जाने लगा है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इस दिवस को शांति और साझेदारी के वैश्विक दिवस के रूप में भी परिवार और मानवीय संबंधों के महत्व को रेखांकित किया जाता है। यह संकेत देता है कि परिवार केवल निजी जीवन की इकाई नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और सामाजिक संतुलन की आधारशिला भी है।

दुनिया भर में संस्कृतियाँ और धर्म अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि पूरी मानव जाति एक बड़ा परिवार है जो एकजुट होकर ही जीवित रह सकती है। इस वर्ष वैश्विक परिवार दिवस की थीम ÷परिवार, शिक्षा और कल्याणः आज और भविष्य÷ इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि परिवार की भूमिका केवल बच्चों को पालने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह शिक्षा का पहला केंद्र और कल्याण का स्थायी आधार है।

वैश्विक परिवार दिवस की प्रासंगिकता इसी बिंदु पर सबसे अधिक उभरकर सामने आती है कि परिवार केवल रहने की व्यवस्था नहीं, बल्कि जीने की संस्कृति है। परिवार में बिताया गया समय निवेश है, व्यय नहीं। बच्चों के साथ संवाद, बुजुर्गों के साथ सहभागिता और रिश्तों के बीच संवेदनशीलता समाज के दीर्घकालिक स्वास्थ्य की गारंटी है। यदि आज परिवार टूट रहे हैं, तो उसका प्रभाव केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह सामाजिक असंतुलन, मानसिक तनाव और मूल्यहीनता के रूप में व्यापक रूप से सामने आएगा। इस संदर्भ में आवश्यक है कि हम परिवार को नए दृष्टिकोण से देखें। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। कार्य और परिवार के बीच प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण हो। डिजिटल सुविधाओं के साथ मानवीय संवाद को भी उतना ही महत्व दिया जाए। बच्चों के लिए समय निकालना दायित्व नहीं, बल्कि भविष्य के समाज में निवेश के रूप में समझा जाए। बुजुर्गों को केवल सहारा नहीं, बल्कि मार्गदर्शक के रूप में पुनः स्वीकार किया जाए।

वैश्विक परिवार दिवस और शांति व साझेदारी का वैश्विक संदेश हमें यह सिखाता है कि परिवार जितना सशक्त होगा, समाज उतना ही शांत और सहयोगी बनेगा। परिवारों में संवाद होगा तो समाज में टकराव कम होंगे। परिवारों में साझेदारी होगी तो राष्ट्रों के बीच भी सहयोग की भावना मजबूत होगी। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपनी पारिवारिक परंपरा को बोझ नहीं, बल्कि वैश्विक समाधान के रूप में देखे। अंततः वैश्विक परिवार दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। यदि परिवार सशक्त हुए तो शांति, साझेदारी और मानवीय मूल्यों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। भारतीय परिवार परंपरा आज भी प्रासंगिक है, आवश्यक है कि हम उसे समयानुकूल रूप देते हुए अपने जीवन के केंद्र में पुनः स्थापित करें, क्योंकि मजबूत परिवार ही मजबूत समाज और शांत विश्व की आधारशिला होते हैं।

यह निजी विचार है।

2025 वर्ष का लेखा-जोखा; क्या खोया क्या पाया

आगत 2026 का स्वागत, विगत 2025 अलविदा

- सुरेश सिंह बैस

वर्तमान दौर में भारत ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को लगातार सुदृढ़ किया है। आर्थिक विकास, विज्ञान-तकनीक, डिजिटल क्रांति, खेल और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ यह संकेत देती हैं कि देश आत्मनिर्भरता और प्रगति के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सन् 2025 भारत के लिए एक तरफउपलब्धियों, प्रगति और आत्मविश्वास का वर्ष रहा तो 2025 में देश के अनेक क्षेत्र में अभी बहुत काम बाकी है। जहाँ देश ने आर्थिक, वैज्ञानिक, डिजिटल, कूटनीतिक और खेल क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कर वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। वर्ष 2025 ने यह स्पष्ट किया कि भारत न केवल विकास की राह पर है, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है।

2025 में भारत ने क्या पाया

राष्ट्रीय व वैश्विक खेल और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया और श्रीलंका के खिलाफबड़ी जीत दर्ज की, जिससे भारतीय खेल के स्तर में मजबूती दिखाई। सामाजिक-आर्थिक बदलाव के क्षेत्र में देखे तो 1 जुलाई 2025 से लागू हुए कई नए वित्तीय नियमों और पॉलिसियों के कारण आम आदमी के लिए बचत और नियम-व्यवस्था में बदलाव आया, जिसे कई लोगों के लिए उपयोगी माना गया। राष्ट्रीय और सुरक्षा क्षेत्र में तैयारी तीव्र गति से बढी है। ऑपरेशन अभ्यास नामक 7 मई 2025 को आयोजित देशव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास से देश की आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तत्परता को और मजबूत किया गया। वैश्विक मंच पर भारत ने प्रभावित करते हुए भारत ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में संतुलित और जिम्मेदार भूमिका निभाई है। विकासशील देशों की आवाज़ को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाने में भारत अग्रणी रहा। विश्व शांति, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका को व्यापक सराहना मिली है।

भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा है। डिजिटल भुगतान प्रणाली, विशेषकर यूपीआई ने देश को डिजिटल लेन-देन में वैश्विक पहचान दिलाई है। स्टार्ट-अप संस्कृति, स्वदेशी उत्पादन और 'मेक इन इंडिया' जैसे अभियानों से रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिला है। विज्ञान और अंतरिक्ष में नई ऊँचाइयाँ प्राप्त कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कम लागत और उच्च तकनीकी क्षमता के साथ कई सफल मिशनों को अंजाम दिया। इससे भारत विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी देशों की श्रेणी में शामिल हुआ है। शिक्षा और युवा शक्ति के रूप में भारत में वैश्विक शक्ति हासिल कर ली। नई शिक्षा नीति के माध्यम से कौशल-आधारित और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर ज़ोर दिया गया है। तकनीकी शिक्षा, स्टार्ट-अप और नवाचार के क्षेत्र में युवा वर्ग की भागीदारी बढ़ी है, जो देश के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है। वही अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। महिला खिलाड़ियों की बढ़ती सफलता और जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं ने खेल जगत में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। सन् 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। महिला और युवा खिलाड़ियों की सफलता ने देश को गौरवान्वित किया। खेलो इंडिया जैसे अभियानों से जमीनी प्रतिभाओं को नया मंच मिला।सामाजिक और पर्यावरणीय पहल के तहत स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं ने आम नागरिक के जीवन स्तर में सुधार किया है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता भविष्य के लिए आशा जगाती है। कुल मिलाकर, भारत की उपलब्धियाँ यह दर्शाती हैं कि देश चुनौतियों के बीच भी विकास, आत्मनिर्भरता और नवाचार के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मजबूत नीतियाँ, युवा शक्ति और तकनीकी प्रगति भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रही हैं। सन् 2025 में भारत विश्व की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहा। औद्योगिक निवेश में वृद्धि, स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों से आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आई। डिजिटल भुगतान प्रणाली और वित्तीय समावेशन ने आम नागरिक की अर्थव्यवस्था में भागीदारी को मजबूत किया। डिजिटल लेन-देन, ई-गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में भारत ने नई उपलब्धियाँ हासिल कीं। यूपीआई और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से भारत विश्व के अग्रणी डिजिटल देशों में शामिल हुआ। सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन होने से पारदर्शिता और सुशासन को बल मिला। स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छता और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं ने करोड़ों नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया। नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदमों ने सतत विकास की नींव को मजबूत किया।कुल मिलाकर सन् 2025 भारत के लिए उपलब्धियों का वर्ष रहा। चुनौतियों के बावजूद देश ने विकास, आत्मनिर्भरता और नवाचार के रास्ते पर निरंतर प्रगति की। भारत की ये उपलब्धियाँ आने वाले वर्षों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती हैं।

2025 में भारत ने क्या खोया

प्राकृतिक आपदा और मानवीय त्रासदी

2025 वर्ष के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी हादसे और अप्रिय घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जानें गईं, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा तैयारियों पर सवाल उठे। देश के कुछ हिस्सों में आतंकवाद और सुरक्षा समस्याएँ बनी रहीं, जिनमें पहलगाम आतंक हमला जैसे घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जवाबी कार्रवाई बढ़ाई। नवंबर 2025 में दिल्ली और आसपास जहरीले स्मॉग की गंभीर स्थिति ने वायु गुणवत्ता के मुद्दे को उभारा, जिससे स्वास्थ्य पर असर हुआ।

सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ता बोझ असहनीय

सड़क सुरक्षा के सारे खराब रिकार्ड भारत, के खाते में हैं। हाईवे आम तौर पर डराते हैं, शहरी और ग्रामीण सड़कों पर दोपहिया वाहन सवार तरह-तरह के जोखिमों के बीच चलते हैं, फुटपाथों की सुरक्षा सरकारें तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पा रहा है ताकि कम से कम पैदल चलने वालों की जान बच सके। नितिन गडकरी ने हाईवे और एक्सप्रेस वे तो बनवाए, लेकिन वह उन्हें सुरक्षित नहीं बना सके। पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि मार्ग दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या पौने दो लाख के करीब पहुंच गई है यानी एक दशक के भीतर लगभग तीन गुनी वृद्धि। 2020 में जब मोटर वाहन एक्ट में कुछ कड़े प्रविधान किए गए थे तो यह कल्पना की गई थी कि इनका कुछ सकारात्मक असर होगा, लेकिन राजनीतिक नुकसान की आशंका में राज्यों में इन्हें भी कुचल दिया गया। इसका मतलब है कि सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी माना गया एक ई यानी इन्फोर्समेंट लचर बना हुआ है। बाकी तीन ई-यानी एजुकेशन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर का भी यही हाल है। बातें दस्तावेज और नोट तक सीमित हैं। समस्या यह है कि नए-नए हस्तक्षेप तो किए जा रहे हैं, लेकिन अनियंत्रित ई रिक्शा और जुवेनाइल ड्राइविंग जैसी नई-नई चुनौतियां भी गंभीर होती जा रही है। हर हादसे को तेज रफ्तार का नतीजा बता देने वाले लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हाईवे और एक्सप्रेस वे तेज 8 साल के इंतजार और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस वर्ष से किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को कैशलेस उपचार की योजना पूरे देश में लागू करने की घोषणा की गई, लेकिन अभी भी यह पायलट प्रोजेक्ट वाले मोड में ही है। हाईवे रफ्तार के लिए ही बनाए जाते हैं। कारों में सुरक्षा के लिए छह एयरबैग्स से लेकर राजमार्गों पर सीसीटीवी कैमरा और एआइ आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग बढ़ाने की बात पर अमल जरूर होने लगा है, ब्लैक स्पाट्स भी पहचान कर सुधारे जा रहे हैं मगर सबसे अधिक जरूरत जनता के बीच वह माहौल बनाने की है जहां गलतियां जानलेवा न बनने पाएं।

हवा भी हुई अब ज़हरीली – 2024 में भारत दुनिया का पांचवां सबसे प्रदूषित देश था। 2025 में भी खास सुधार नहीं हुआ जबकि वायु प्रदूषण को भारत में जीवन प्रत्याशा के लिए सबसे बड़ा बाहरी खतरा बताया गया है! दरअसल वायु प्रदूषण अब पूरे देश का संकट है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के छोटे शहर हो या फिर दिल्ली-मुंबई जैसी मेगासिटी, जहरीली हवा हर जगह है। एक और साल जहरीली हवा में सांस ले ही बीता...इस धुंधली आस में कि शायद जिम्मेदार जागें और जहरीली हवा से निपटने का उपाय करेंगे।

देश की राजधानी और एनसीआर के अन्य शहरों की हवा में साल दर साल जहर, बढ़ता ही जा रहा है। एनकैप और ग्रेप के बावजूद यहां सदी की शुरुआत के साथ एक स्वास्थ्य आपातकाल सी स्थिति बन जाती है। अस्पतालों में सांस और गले संबंधी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। अब तो मास्क भी जैसे एनसीआर के वायु प्रदूषण के सामने दम तोड़ रहे हैं। छोटे बच्चे न तो स्कूल जा पा रहे हैं, न घर-आंगन-पार्क में खेल पा रहे हैं। मगर सरकारें मानो गहरी निद्रा में है। केवल बातें हो रही है वर्षों से। जो कथित उपाय किए जाने का दावा है, वे भी फौरी ही है। बड़ी विडंबना यह कि वायु प्रदूषण के जो अहम कारक है, उन पर खास ध्यान ही नहीं है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़क से उड़ती धूल, कोयला और उपले का बेरोकटोक उद्यमों और घरेलू स्तर पर प्रयोग और निर्माण कार्यों से उत्पन्न हो रहे प्रदूषक, इनके संबंध में तो जैसे कोई जिम्मेदार सोच ही नहीं रहा। लंबे समय तक पराली को एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताया जाता रहा जबकि उसकी हिस्सेदारी बहुत कम थी। दिल्ली में जाम के कारण हालात और खराब है। वाहन रेंगने पर विवश है और उनका काला धुआं हवा में जहर बनकर जीवन लील रहा है।

न्यायपालिका बढ़ते मामलों की लंबी फेहरिस्त

सुप्रीम कोर्ट रोजाना चर्चा में होता है। जाहिर तौर पर कई बड़े फैसले भी होते हैं लेकिन चर्चा इसलिए ज्यादा होती है कि केस या तो टल जाते है या फिर प्राथमिकता में ही नहीं आ पाते। बड़े फैसलों के लिहाज से भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में 2025 को एक असाधारण वर्ष कहा जा सकता है क्योंकि इस साल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही पीठ के एक फैसले को पलट दिया और कहा कि कोर्ट विधेयकों पर निर्णय लेने के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा नहीं तय कर सकता।

इस फैसले ने न्यायपालिका को उसकी हद बताई क्योंकि सुप्रीमकोर्ट के ही दो न्यायाधीशों की पीठ नेइसी साल विधेयकों पर कैसला लेने के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन तय कर दी थी। यह सब कुछ महज डेढ़ दो महीनों में हो गया, लेकिन दुख की बात यह है कि कई मुख्य न्यायाधीशों की ओर से खुद लंबित मामलों को लेकर चिंता जताने और इसे दूर करने की बात करने के बाद भी बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है। भारत में न्याय की धीमी प्रक्रिया एक गंभीर और बहु-स्तरीय समस्या है, जिससे आज भी निजात पाना बाकी है। जस्टिस संजीव खन्ना कहते हैं कि 5.0 करोड़ मुकदमे लंबित है भारत भर के न्यायालयों में, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राज्यसभा में दिए उत्तर के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय की ही बात करें तो यहां दिसंबर 2025 तक कुल 90, 897 मुकदमे लंबित हैं। हर बार जब नए-न्यायाधीश आते हैं, इस वर्ष तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर तीन बार नियुक्ति हुई, उनकी पहली प्राथमिकता और चिंता वादों का शीघ्न निस्तारण होती है। मगर परिणाम नहीं दिखता।

सफेदपोश आतंकी: आए नए रूप में भारत में प्रायोजित आतंकवाद के पीछे बैठे शातिर लोग आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए हमेशा से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते रहे हैं, जो सामान्यतया कट्टरता का पाठ पढ़ते थे, आर्थिक प्रलोभनों के कारण आत्मघाती प्यादों की तरह इस्तेमाल होते थे, लेकिन इस साल मदरसे और मौलवियों की कट्टरता से आगे बढ़ते हुए भारत में पहली बार सक्रिय रूप से आतंकवाद का सफेदपोश चेहरा भी सामने आया है। जम्मू- -कश्मीर में डाक्टरों से जुड़े आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के माड्यूल के पर्दाफाश, उनके ठिकाने से 3000 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक की बरादगी और दिल्ली में लाल किला के सामने एक डाक्टर द्वारा आत्मघाती धमाके को अंजाम दिए जाने की घटना ने जनमानस को

झकझोर दिया, लेकिन चिंता बढ़ाने वाली बात यह भी रही कि पढ़े-लिखे प्रोफेशनल द्वारा हथियार उठाने और आत्मघाती हमला करने की घटना पहली बार सामनें आई। आतंकवाद के सफेदपोश चेहरे ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी करने के साथ ही उनके द्वारा युवाओं को कट्टरता से दूर करने की रणनीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर दिया। अभी तक एजेंसियों का जोर मदरसों, मौलवियों और इमामों के सहारे युवाओं को कट्टरता से बचाने के लिए अभियान चलाए जाने पर था। अब एजेंसियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून, एमबीए व अन्य प्रोफेशनल कोर्स बाले संस्थानों पर भी नजर रखनी होगी और वहां पढ़ने वाले युवाओं को कट्टरता से बचाने की कोशिश करनी होगी।

पहलगाम/आपरेशन सिंदूर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या की घटना के बाद दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का दंश झेलते आ रहे भारत ने अपने धैर्य की अंतिम सीमा रेखा खींच दी। पहलगाम के आतंकी गुनहगारों के साथ पाकिस्तान को सख्त संदेश देने के लिए भारत ने छह-सात मई, 2025 की रात आपरेशन सिंदूर की सैन्य कार्रवाई की शुरूआत कर पाक अधिकृत कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान के भीतर आतंक के नौ बड़े ठिकानों को ध्वस्त करने के साथ करीब 100 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस कार्रवाई के जरिए भारत ने पाकिस्तान के इस भ्रम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि वह उसकी सरजमीं पर पनपे आतंकी ठिकानों पर सीधे सैन्य हमला नहीं करेगा। भारत ने आपरेशन सिंदूर के जरिए साबित कर दिया कि पाकिस्तान में स्थित सभी आतंकी ठिकानों तक वह पहुंच सकता है। यह एक ऐसी सामरिक कार्रवाई थी, जिसने भारत के सुरक्षा सोच को धैर्य' से' प्रतिकार की दिशा में निर्णायक मोड़ दिया। आपरेशन सिंदूर महज एक जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की यह घोषणा है कि वह सीमाधार आतंकवाद को अपनी संप्रभुता पर हमला तथा युद्ध मानेगा। भारत अब शातिको केवल आदर्श नहीं समझता, बल्कि उसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शक्ति और साहस भी रखता है।

भविष्य में जब रणनीतिक-सामरिक इतिहासकार इस कालखंड पर गौर करेंगे तो बेशक आपरेशन सिंदूर को नार भारत की उभरती रणनीतिक चेतना का निर्णायक मोड़ मानेंगे। इस आपरेशन के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने एक नई शुरुआत की और तीन दर्जन से ज्यादा देशों में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेजकर उन्हें अपने सोच के साथ जोड़ लिया।

आनलाइन फ्राड और लालच का साइबर जाल

धोखाधड़ी मानव सभ्यता के इतिहास के सबसे पुराने अपराधों में से एक रही है। सोचने-समझने की शक्ति विकसित होने के साथ ही इंसानों से यह अपराध होना शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक देशकाल, परिस्थितियों के हिसाब से इसमें बदलाव आता गया। आज के तकनीकी युग में इस अपराध ने एक ऐसा जामा पहन लिया है जिसमें आपके साथ हो रहे अपराध का आपको आभास ही नहीं होता और जब होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। **यह निजी विचार है।**

ट्रांसमिशन कंपनी से अधीक्षण अभियंता सहित 7 कर्मियों की विदाई

कर्मियों का अनुभव हमारी बहुमूल्य पूंजी - ईडी श्री एम.एस.चौहान

रायपुर।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी डंगनिया मुख्यालय के भारप्रेषण कक्ष में आज अधीक्षण अभियंता सहित 7 अधिकारी-कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् विदाई दी गई। इस अवसर पर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक (वित्त) श्री एम.एस.चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विदाई समारोह में मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) श्री ए.एम.परियल, मुख्य अभियंता (भार प्रेषण) श्रीमती शारदा सोनवानी, मुख्य अभियंता (एस.एंड पी) श्री केबी पात्रे, मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट) श्री प्रसन्ना गोसावी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री एच.एल.पंचारी ने संयुक्त रूप से सेवानिवृत्तजनों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृतिचिन्ह भेंट कर उनके सुखमय जीवन की कामना की।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (वित्त) श्री चौहान ने बिजली कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए हुए कहा कि बिजली कर्मियों के पास

बहुमूल्य अनुभव की पूंजी है और उनके योगदान से हम उपभोक्ता संतोंष के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं।

आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों में अधीक्षण अभियंता श्री अरूण कुमार चक्रवर्ती खेदामारा भिलाई, अधीक्षण अभियंता श्री नरेंद्र कुमार बिसेन रायपुर, निज सचिव श्री के. श्रीनिवास बिलासपुर, अनुभाग अधिकारी श्री भीष्म प्रसाद तिवारी रायपुर, लाइन सहायक श्रेणी- एक श्री राम दयाल साहू भिलाई, लाइन सहायक श्रेणी- एक श्री ए. गोविंद राजू बिलासपुर, कनिष्ठ पर्यवेक्षक (परीक्षण) श्री जी.ई. हैरिस कोरबा शामिल हैं। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन कार्यपालन अभियंता (पी.एंड एस.) श्री पंकज चौधरी तथा संचालन प्रबंधक (जनसंपर्क) श्री गोविंद पटेल ने किया। सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों ने सेवा के दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई

तमिलनाडु से जुड़े अधिकारियों ने मंत्रालय में हिंदी के प्रचार-प्रसार को नई गति दे दी, ये एक भारत, श्रेष्ठ भारत का उदाहरणः डॉ. जितेंद्र सिंह

हिंदी केवल भाषा नहीं राष्ट्रीय एकता की जीवंत अभिव्यक्ति डॉ. जितेंद्र सिंह

पीआईबी

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आज पृथ्वी भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री, पृथ्वी विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने की। बैठक में हिंदी के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान के व्यापक प्रसार, जनभागीदारी को सशक्त बनाने तथा राष्ट्रीय एकता के भाव को और सुदृढ़ करने पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और समावेशी संवाद का माध्यम है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति की यह बैठक देश की बहुभाषिक आत्मा और राष्ट्रीय एकता की सशक्त झलक पेश करती है। केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के सचिव एवं सहायक सचिव को बधाई देते हुए कहा कि तमिलनाडु से जुड़े अधिकारियों के नेतृत्व में मंत्रालय में हिंदी के प्रचार-प्रसार को नई गति मिली है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर यह भी उल्लेख किया कि लगभग दो दशकों के बाद ऐसा सुखद संयोग बना है कि मंत्रालय में तमिलनाडु से जुड़े अधिकारियों के माध्यम से हिंदी कार्यों को संगठित रूप से आगे बढ़ाया जा सका है, जो ÷एक भारत, श्रेष्ठ भारत÷ की भावना को और मजबूत करता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विज्ञान को आम जन तक पहुंचाने के लिए भाषा का सरल, सुलभ और सटीक होना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैज्ञानिक शब्दावली की मूल पहचान बनाए रखते हुए हिंदी के माध्यम से संचार को बढ़ावा देना ही मंत्रालय का उद्देश्य है, ताकि छात्रों और शोधार्थियों को किसी भी स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान न हो। उन्होंने बताया कि अनुवाद के कामों में अब भाषाविदों के साथ-साथ विषय विशेषज्ञों को भी जोड़ा जा रहा है, जिससे अनुवाद की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि 21वीं सदी के उन भारतीय वैज्ञानिकों को भी प्रमुखता दी जाए, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा को नई पहचान दी है। इसके लिए मंत्रालय द्वारा आधुनिक भारतीय वैज्ञानिकों पर आधारित एक डिजिटल रिपॉजिटरी विकसित करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे शोध, नीति निर्माण और जनसंपर्क में सुविधा मिले।

बैठक में सुझावों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर क्विज प्रतियोगिताएं और चैलेंज-आधारित आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि डीप ओशन मिशन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों पर विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित कर उन्हें वैज्ञानिक सोच से जोड़ा जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक चयन की एक पारदर्शी प्रणाली विकसित कर, बढ़िया प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और सहभागिता बढ़े।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हाल के वर्षों में हिंदी का विस्तार स्वाभाविक और मांग-आधारित रहा है। उन्होंने बताया कि कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हिंदी जानने वाले युवाओं को प्राथमिकता मिलने लगी है, जिसका प्रभाव तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों तक स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि हिंदी अब रोजगार और अवसरों की भाषा के रूप में भी उभर रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत की विकास यात्रा का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। उन्होंने डीप ओशन मिशन, तटीय अनुसंधान, भूकंपीय अध्ययन और मौसम विज्ञान से जुड़े कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में ये पहल भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक क्षमता को नई ऊंचाऊ देंगी। उन्होंने विश्वास जताया किया कि जिस प्रकार अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत वैश्विक पहचान बना रहा है, उसी प्रकार समुद्र विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा।

डॉ जितेंद्र सिंह ने हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों से आह्वान किया कि वे औपचारिक बैठकों के अलावा भी अपने सुझाव पत्र, ई-मेल अथवा प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से मंत्रालय तक पहुंचाते रहें, जिसके बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी व्यवहारिक सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

मोदी कैबिनेट ने ओडिशा में NH-326 चौड़ीकरण परियोजना को दी मंजूरी, 1526 करोड़ रु. होंगे खर्च

पीआईबी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-326 को चौड़ा करने और उन्नत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस परियोजना के तहत मौजूदा दो-लेन वाले राजमार्ग को ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) माध्यम से 68.600 किलोमीटर से बढ़ाकर 311.700 किलोमीटर का दो-लेन वाला राजमार्ग बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग-326 (ह्न-326) के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर कुल 1,526.21 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे श्वक्ष्ट (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) मोड में पूरा किया जाएगा।

दक्षिण ओडिशा को मिलेगा बड़ा लाभ - NH-326 को अपग्रेड करने से यात्रा तेज,सुरक्षित और सुगम होगी। इसका सबसे अधिक लाभ गजपति,रायगढ़ा और कोरापुट जिलों को मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय लोगों को बाजार,स्वास्थ्य सेवाओं,शिक्षा संस्थानों, पर्यटन स्थलों और रोजगार तक आसान पहुंच मिलेगी,जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा।

इस परियोजना के तहत NH-326 को NH-26,NH-59,NH-16 और रायपुर-विशाखापत्तनम कॉरिडोर से बेहतर ढंग से जोड़ा जाएगा। इससे गोपालपुर पोर्ट, जेपोर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों तक अंतिम-छोर संपर्क मजबूत होगा।

यह मार्ग NALCO, वेदांता, उत्कल एल्युमिना, आईएमएफए, जेके पेपर, एचएएल, मेगा फूड पार्क जैसे औद्योगिक केंद्रों और केंद्रीय ओडिशा विश्वविद्यालय,कोरापुट मेडिकल कॉलेज,तप्तपानी जैसे शिक्षा-पर्यटन स्थलों को जोड़ता है।

ये फायदे भी होंगे

यात्रा समय में 2.5 से 3 घंटे की बचत होगी, वहीं दूरी में लगभग 12.5 किमी की कमी हो जाएगी। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा में सुधार और परिवहन लागत में कमी भी होगी। इस निर्माण कार्य को 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद 5 साल की मेंटेनेंस अवधि होगी। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि इस मार्ग को 14 अगस्त 2012 को अधिसूचना के जरिए ह्न-326 घोषित किया गया था। यह सड़क मोहन, रायगढ़ा, लक्ष्मीपुर और कोरापुट जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ते हुए ओडिशा के भीतर और आंध्र प्रदेश से संपर्क को मजबूत करती है।

किरोड़ीमल कालोनी हुआ राममय,श्री राम की भक्ति में डूबे श्रद्धालु

अखंड रामायण पाठ का हुआ भव्य आयोजन

रायगढ़/लोकशक्ति।

एक ओर जहां नववर्ष के स्वागत में शहर भर में विविध रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वहीं स्थानीय किरोड़ीमल कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में नववर्ष के आगमन को भारतीय परंपरा और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाने की एक सशक्त परंपरा बीते 28 वर्षों से निरंतर निभाई जा रही है। पूर्व विधायक स्वर्गीय रोशनलाल अग्रवाल की प्रेरणा से वर्ष 1998 में शुरू हुई यह परंपरा आज भी पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ जारी है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी मोहल्लेवासियों के सामूहिक सहयोग से अखंड रामायण पाठ का भव्य आयोजन संपन्न हुआ।

24 घंटे चला अखंड रामायण पाठ

गौरतलब हो कि स्थानीय किरोड़ीमल कॉलोनी में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान लगातार 24 घंटों तक अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध पंडितों द्वारा श्रीराम कथा का सस्वर वाचन किया गया, जिसे सुनने के लिए मोहल्लेवासियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए जलपान की समुचित व्यवस्था भी आयोजकों द्वारा की गई थी।अखंड रामायण पाठ के समापन के पश्चात् विधिवत प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत मधुर भजनों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। बच्चों

की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम की भक्ति में भाव-विभोर कर दिया।

भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश

उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में नववर्ष के अवसर पर कई स्थानों पर पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े आयोजनों के साथ-साथ युवा वर्ग में नशे जैसी कुरीतियां भी देखने को मिलती हैं। ऐसे में स्वर्गीय रोशनलाल अग्रवाल की प्रेरणा से प्रारंभ किया गया यह अखंड रामायण पाठ का आयोजन एक सकारात्मक सामाजिक संदेश देता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नववर्ष को भारतीय धार्मिक परंपराओं के अनुरूप मनाते हुए युवाओं को गलत लतों से दूर रहने और संस्कारों से जुड़ने की प्रेरणा देना रहा है।

प्रेरणादायक परंपरा

किरोड़ीमल कॉलोनी में विगत 28 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहा यह अखंड रामायण पाठ न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का भी सशक्त उदाहरण है। नववर्ष के अवसर पर इस तरह के धार्मिक आयोजनों में सहभागिता से जहां युवाओं का मनोबल बढ़ता है, वहीं समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सद्भाव का वातावरण भी निर्मित होता है।

सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत बाजार पहुंच सहायता पहल शुरू की

पीआईबी

सरकार ने आज निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) के अंतर्गत बाजार पहुंच सहायता (एमएएस) पहल की शुरुआत की है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 नवंबर, 2025 को अनुमोदित एक प्रमुख पहल है। बाजार पहुंच सहायता पहल को निर्यात प्रोत्साहन मिशन की निर्यात दिशा उप-योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्?म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, पहली बार निर्यात करने वालों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच को मजबूत करना है।

निर्यात प्रोत्साहन मिशन (एमएएस) का संचालन वाणिज्य विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड और अन्य उद्योग संघों के समन्वय से संयुक्त रूप से किया जाता है। बाजार पहुंच सहायता का उद्देश्य संरचित और परिणामोन्मुखी बाजार पहुंच संबंधी उपायों के माध्यम से खरीदारों से बेहतर संपर्क स्थापित करना तथा वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करना है।

बाजार पहुंच सहायता हस्तक्षेप के अंतर्गत, क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम), अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, भारत में आयोजित मेगा रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकों (आरबीएसएम) और प्राथमिकता वाले तथा उभरते निर्यात बाजारों में व्यापार प्रतिनिधिमंडलों सहित गतिविधियों के लिए संरचित वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रमुख बाज़ार पहुंच कार्यक्रमों का तीन से पांच साल का एक दूरदर्शी कैलेंडर पहले से तैयार और अनुमोदित किया जाएगा, जिससे निर्यातकों और आयोजन एजेंसियों को समय से काफी पहले भागीदारी की योजना बनाने और बाज़ार विकास प्रयासों की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। समर्थित कार्यक्रमों में कम से कम 35 प्रतिशत सूक्ष्?म, लघु एवं मध्?यम उद्यमों की भागीदारी अनिवार्य की गई है, जिसमें निर्यात विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए नए भौगोलिक क्षेत्रों और छोटे बाज़ारों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। प्रतिनिधिमंडल का आकार कम से कम 50 प्रतिभागियों का निर्धारित किया गया है, जिसमें बाज़ार की स्थितियों और रणनीतिक प्रासंगिकता के आधार पर लचीलापन प्रदान किया जाएगा।

आयोजन स्तर पर वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा और लागत-साझाकरण अनुपात को युक्तिसंगत बनाया गया है और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा बाजारों को तरजीही सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले वर्ष में 75 लाख रुपये तक के निर्यात कारोबार वाले छोटे निर्यातकों को नए और छोटे निर्यातकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आंशिक हवाई किराया सहायता प्रदान की जाएगी। आयोजन की सूचीकरण, प्रस्ताव प्रस्तुत करने, अनुमोदन, प्रतिभागियों को शामिल करने, निधि जारी करने और निगरानी से संबंधित सभी प्रक्रियाएं https\Ñ//trade.gov.in के माध्यम से सुगम बनाई जाएंगी, जिससे सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता और सुगम पहुंच सुनिश्चित होगी। प्रत्येक समर्थित कार्यक्रम में भाग लेने वाले निर्यातकों के लिए अनिवार्य ऑनलाइन फीडबैक तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें खरीदार की गुणवत्ता, उत्पन्न व्यावसायिक अवसरों और बाजार प्रासंगिकता जैसे मापदंडों को शामिल किया जाएगा। फीडबैक और कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर, बाजार पहुंच सहायता दिशा-निर्देशों को धीरे-धीरे परिष्कृत और संस्थागत रूप दिया जाएगा। मौजूदा बाजार पहुंच संबंधी उपायों के पूरक के रूप में, संभावित विदेशी खरीदारों, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-प्रधान, उभरते और नवविकास क्षेत्रों में, के लिए अवधारणा प्रमाण और उत्पाद प्रदर्शन हेतु एक नए घटक की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

अपराध रोकने के साथ निकले तबके के लोगों तक पहुंची जिले की पुलिस

उपहार योजना से पुलिसिंग कार्यशैली में दिखा बदलाव

एसपी विजय कुमार पांडे ने पत्रकारों के समक्ष पेश किया साल भर की लेखा -जोखा

जांजगीर-चांपा -

इस वर्ष जिले में पुलिस का कार्य अपराध की रोकथाम तक ही सीमित न रहकर उपहार योजना की माध्यम से आमजन तक पहुंचने का भी रहा है जिसका जिले में पुलिस के प्रति आमजन की नजरिया में बदलाव देखने को मिला है। आज पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने पत्रकारों के समक्ष साल भर की अपराधों व कार्यो की लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि हमने अपराध रोकने के साथ उपहार योजना से अक्षम लोगों तक पहुंचकर उन्हे स्वरोजगार योजना से जोड़ने के साथ सुरक्षा के हेलमेट वितरण किया है । इस दौरान उन्होंने विभिन्न मामलों में पुलिस की सफ्लता और असफ्लता पर खुलकर बात करते हुए अलग अलग अपराधों का आंकड़ा प्रस्तुत किया। उक्त आंकड़े में इस साल हत्या की कुल 29 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें से 24 मामलों का निराकरण कर लिया गया है , शेष अन्य मामलों में छानबीन जारी होने की बात बताई । इसी तरह हत्या के प्रयास के कुल 33 मामले दर्ज हुए, जो पिछले बार की अपेक्षा 6 अधिक है जिसमें 9 मामले अनसुलझे है। पिछले साल अपहरण के 186 मामले दर्ज हुए थे, जो बढ़कर इस बार 231 हो गए जिसमें 111 मामलों का निराकरण हुआ है, जबकि अन्य मामलों में छानबीन चल रही है। लूट के कुल 23 मामले दर्ज किए गए जो पिछले साल के मुकाबले 6 अधिक है जिसमें 19 मामलों को सुलझा लिया गया है। चोरी और नकबजनी के मामलों में पिछले साल के मुकाबले काफी कम अपराध दर्ज हुए हैं वहीं वर्ष भर में बलात्कार के कुल 147 मामले दर्ज हुए हैं जो पिछले साल की अपेक्षा 30 मामले अधिक है जिसमें 111 मामलों का निराकरण कर लिया गया है जबकि शेष में जांच और कार्रवाई जारी है। आबकारी एक्ट के कुल 1507 मामले दर्ज हुए हैं जो पिछले साल के मुकाबले 100 अधिक है। दुसरी तरफजिले में रफ्तार का कहर भी देखने को मिला और साल भर के आंकड़ों पर गौर करें तो कुल 511 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 239 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 436 लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचे। एसपी विजय कुमार पांडे ने बताया जिले में दुर्घटना का प्रमुख कारण शराब पीकर तेज गति से वाहन चलना है। इसके साथ नेशनल व स्टेट हाईवे के मुकाबले गांवों की सड़कों पर ज्यादा दुर्घटनाएं हुई है। दुर्घटना में मौत की प्रमुख वजह समय पर इलाज नहीं हो पाना भी है। यदि यहां ट्रामा सेंटर की स्थापना हो जाए तो मौतों का आंकड़ा बहुत हद तक काम किया जा सकता है , वहीं उन्होने पिछले साल की तुलना में 6 प्रतिशत अपराध अधिक होना भी स्वीकार किया है। आज की पत्रकार वार्ता व मिलन समारोह में एसपी विजय कुमार पांडे सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार एवं नगर पुलिस अधीक्षक मैडम मौजूद रहे।

अवैध रेत उत्खनन, परिवहन व भंडारण पर कार्रवाई : 01 चैन माउंटेन व 02 ट्रैक्टर जब्त

जांजगीर-चांपा

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में खनिज टास्क फ ोर्स द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण करने वाले वाहनों, स्थानो का औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की गई।

तहसील बम्हनीडीह अंतर्गत ग्राम बिर्रा में अवैध परिवहन में संलिप्त पाए जाने पर 2 ट्रैक्टर को जब्त कर थाना के सुपुर्द किया गया। साथ ही तहसील जांजगीर के केवा-नवापारा में अवैध रेत खनन करने वाली 01 चैन माउंटेन जब्त की गई। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन,भण्डारण करने वालो के विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत कार्यवाही की गई है।

ऑनलाइन 24×7 टोकन सुविधा से आसान हुई धान खरीदी

3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और पारदर्शी व्यवस्था से धान विक्रय हुआ आसान

किसान हितैषी विष्णु का सुशासन - किसान श्री भीम

जांजगीर-चांपा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की सशक्त मिसाल बन रही है। योजना के अंतर्गत 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हो रही धान खरीदी, साथ ही धान खरीदी केंद्रों में की गई बेहतर, सरल और सुगम व्यवस्थाओं ने किसानों का भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ाया है।

इसी कड़ी में जिले के ग्राम सुकली निवासी किसान श्री भीम गोंड़ की कहानी इसी सुशासन और किसान-हितैषी व्यवस्था की जीवंत मिसाल है। वर्षों की मेहनत, आधुनिक खेती के अनुभव और शासन की पारदर्शी प्रणाली का परिणाम रहा कि उन्होंने धान खरीदी केंद्र पेंड्री में 116 क्विंटल धान का सफ्लतापूर्वक विक्रय किया। किसान भीम गोंड़ बताते हैं कि इस वर्ष ऑनलाइन 24म7 टोकन व्यवस्था ने पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया। न तो भीड़ का सामना करना पड़ा, न ही लंबी कतारों में समय गंवाना पड़ा। तय समय पर केंद्र पहुँचते ही नमी परीक्षण, तौल और विक्रय की सभी प्रक्रियाएँ सहजता से पूर्ण हो गईं। समय पर भुगतान मिलने से उन्हें यह विश्वास हुआ कि अब किसान अपनी उपज पूरे आत्मसम्मान और निश्चिंतता के साथ बेच पा रहे हैं। किसान श्री भीम गोंड़ की सफ्लता यह सिद्ध करती है कि जब किसान की मेहनत और सुशासन की व्यवस्थाएँ साथ-साथ चलती हैं, तो खेती केवल आजीविका नहीं, बल्कि सम्मानजनक आय और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनती है।

प्रोजेक्ट आओ खेल खेलें की हुई शुरूआत, बच्चों व ग्रामीणों में खेल भावना को मिलेगा बढ़ावा

रायपुर,। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप जिले में बच्चों तथा जनसामान्य के बीच खेल भावना विकसित करने एवं पंचायत स्तर पर मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट आओ खेल खेलें का शुभारंभ किया गया है। सुशासन दिवस के अवसर पर रायपुर जिले के विकासखंड धरसीवां अंतर्गत 35 ग्राम पंचायतों सहित परसतराई एवं दोनदेखुर्द में इस परियोजना की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों तथा स्कूली छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में संचालित प्रोजेक्ट आओं खेल खेलें का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करना, स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना तथा पंचायतों को मनोरंजन और सकारात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाना है। प्रोजेक्ट आओं खेल खेलें से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ-साथ सामाजिक समरसता को भी मजबूती मिलेगी।

सिवनी च की रूखमणी पाण्डेय बनी लखपति दीदी - आत्मनिर्भरता की बनी मिसाल

बिहान योजना से बदली जिंदगी, समूह से मिली पहचान और सम्मान

जांजगीर-चांपा विकासखंड बलौदा अंतर्गत ग्राम सिवनी (च) की रहने वाली श्रीमती रूखमणी पाण्डेय आज ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की प्रेरक पहचान बन चुकी हैं। कभी एक सामान्य गृहिणी के रूप में पूरी तरह परिवार पर आश्रित रहने वाली रूखमणी पाण्डेय आज हर महीने 15 से 20 हजार रुपये की आय अर्जित कर न केवल अपने परिवार को संबल दे रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। श्रीमती रूखमणी पाण्डेय के पति पशुपालन का व्यवसाय करते थे, लेकिन कोरोनाकाल और लॉकडाउन के दौरान हुए भारी नुकसान के कारण यह व्यवसाय लगभग बंद होने की स्थिति में आ गया। आर्थिक कठिनाइयों के इस दौर ने रूखमणी के भीतर कुछ नया करने और परिवार की जिम्मेदारी में भागीदार बनने की प्रेरणा जगाई।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ÷बिहान÷ अंतर्गत लखपति दीदी पहल से जुड़ने के बाद रूखमणी पाण्डेय के जीवन में निर्णायक बदलाव आया। गांव में आरबीके दीदी के सहयोग से उन्होंने अपने आसपास की महिलाओं को एकजुट कर जय अम्बे महिला स्व सहायता समूह, सिवनी (च) का गठन किया। 25 फरवरी 2020 को गठित यह समूह उन्नति महिला ग्राम संगठन सिवनी (च) और बिहान महिला क्लस्टर संगठन कुरदा से जुड़ा हुआ है। समूह के माध्यम से रूखमणी पाण्डेय को बैंक लिंकेज के तहत 1 लाख रुपये तथा समूह से अतिरिक्त ऋण प्राप्त हुआ। इस आर्थिक सहयोग से उन्होंने अपने परिवार के पुराने पशुपालन व्यवसाय को पुनः शुरू किया, साथ ही आचार, पापड़, मसाला और अगरबत्ती निर्माण जैसी विविध आजीविका गतिविधियों की शुरुआत की। जिससे श्रीमती रूखमणी पाण्डेय न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, बल्कि अपनी छोटी-बड़ी जरूरतें स्वयं पूरी कर रही हैं। वे अपने समूह की अन्य महिलाओं को भी आजीविका गतिविधियां अपनाने के लिए लगातार प्रेरित कर रही हैं।

श्रीमती रूखमणी पाण्डेय ने कहा कि ÷लखपति दीदी पहल ने मुझे आत्मविश्वास दिया, पहचान दी और अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया। इसके लिए मैं केंद्र एवं राज्य सरकार का हृदय से धन्यवाद करती हूं। आज रूखमणी पाण्डेय की सफ्लता की कहानी यह साबित करती है कि सही मार्गदर्शन, समूह की ताकत और सरकारी योजनाओं के सहयोग से ग्रामीण महिलाएं भी आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख सकती हैं।

हथनेवरा 15 दिवसीय ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण संपन्न

जांजगीर-चांपा

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में महिलाओं, बालिकाओं में कौशल विकास करने एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तथा समान अवसर एवं भागीदारी प्रत्येक बिटिया हो सक्षम थीम पर विकासखण्ड बम्हनीडीह अंतर्गत ग्राम-हथनेवरा आंगनबाड़ी केन्द्र 04 में 15 दिवसीय ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल ने बताया कि ब्युटी पार्लर प्रशिक्षक सुश्री अंजली अग्रवाल एवं साथी ऐश्वर्या, लैक्मे अकैडमी, बिलासपुर के द्वारा प्रशिक्षार्थी महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं निरंतर 15 दिवस सौंदर्य सेवाओं के अनेक पहलुओं के अभ्यास की परीक्षा ली गई। जिसमें लिखित एवं मौखिक प्रश्न पूछे गए, प्रशिक्षण की सार्थकता सिद्ध करने प्रत्येक प्रशिक्षार्थी से मौखिक परीक्षा में-स्कीन टोन पहचान करना, मेकअप, थ्रेड, कलर कॉम्बिनेशन बनाना, वैक्सिंग, आदि पूछा गया तथा वैक्सिंग, हेयर कटिंग, अपरलिप्स, थ्रेडिंग, मेकअप प्रोसेस आदि पर प्रायोगिक परीक्षा ली गई। परीक्षा में सभी प्रशिक्षार्थियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया जिसके उपरांत सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया।

कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल के द्वारा सभी प्रशिक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उत्साह वर्धन किया गया एवं आने वाले रामय में अपने सीखे कौशल को एक प्लेटफार्म देने और आर्थिक रूप से सक्षम बनने के लिए विभाग की महिला कोष एवं ऋण योजना के अंतर्गत प्रावधानों से अवगत कराते हुए आगे बढ़ने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजरों से संपर्क करने की जानकारी दी गई। इस दौरान परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बम्हनीडीह श्रीमती ऋचा तिवारी, पर्यवेक्षक श्रीमती रजनी साहू, केन्द्र प्रशासक, सखी वन स्टॉप सेंटर सुश्री एच. निशा खान, सरपंच श्री दुष्यंत सिंह सहित संबधित अधिकारी कर्मचारी, महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं लाभान्वित हुए।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत लघु व्यवसाय हेतु ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित

जांजगीर-चांपा

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित जांजगीर-चांपा द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से बैंक प्रवर्तित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के तहत लघु व्यापार एवं व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना अंतर्गत किराना, मनिहारी, कपड़ा दुकान, नाई सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैंसी स्टोर, मोटर मैकेनिक, साइकिल मरम्मत, टीवी-रेडियो-मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोनापत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अन्य आयजनक व्यवसायों के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाता है। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित ने बताया कि इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर व्यवसाय करना चाहता है, उस स्थान पर चलने वाले व्यवसाय अथवा उपरोक्त व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य व्यवसाय हेतु आवेदन किया जा सकता है, आवेदक को व्यवसाय का सामान्य अनुभव, जानकारी होना चाहिए। आवेदक योजना में ऋण की स्वीकृति बैंक द्वारा दी जावेगी। व्यवसाय अनुसार न्यूनतम 1,00,000 लाख रू. तक के ऋण प्रकरण में स्वीकृत ऋण के विरूद्ध 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 50,000 जो भी कम हो अनुदान राशि जिला अंत्यावसायी विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

जांजगीर पैंथर फुटबाल लीग में पहुंचा पहले नंबर पर

जांजगीर चांपा / हाई स्कूल मैदान में स्व श्री राम कुमार पाण्डेय स्मृति रात्रि कालीन फुटबाल प्रतियोगिता के लीग मुकाबले में जांजगीर पैंथर पहले स्थान पर बढ़त हासिल करते हुए जांजगीर चैम्पियन को दूसरे स्थान पर धकेलते हुए बढ़त हासिल कर लिया है । आज खेले गए मुकाबले में जांजगीर पैंथर ने राजा मोबाइल टीम को 3-0 हरा दिया वहीं जांजगीर चैंपियन ने अपने दूसरे मुकाबले में मड़वा एफसी को 4-0 से हरा कर दूसरे स्थान पर बढ़त बना रखी है। आज अपने टीम के खिलाड़ियों को टीम के ओनर ई. रवि पाण्डेय ने शुभकामनाएं देने फुटबाल प्रतियोगिता स्थल पर मौजूद रहे तथा अन्य मैचों में खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी । इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य अनिल राठौर अधिवक्ता अमितेश राठौर राहुल भवानी, श्यामा, दीपक राकेश, रवि श्रीवास,वाशु राठौर, सौरभ सिंह, जयंत, विक्की, सुमित, मास्टर, प्रेम शंकर सिंह राठौर, श्रीजन, रामानुज, गौरेश, पुत्रा, सुनील खरे , एवम् जिला फुटबाल संघ जांजगीर के अन्य लोग उपस्थित रहे।

नया साल से पहले एसपी ने किया बड़ा बदलाव

थाना प्रभारी सहित पच्चीस पुलिस कर्मियों का हुआ तबादला

जांजगीर-चांपा /

नया साल से पहले पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने जिले की थाना चौकी के प्रभारों में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है जिसमें 25 पुलिस कर्मी इधर से उधर हुए हैं । इस थोक तबादले से पूरे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता को थाना प्रभारी चांपा से जांजगीर, निरीक्षक अशोक वैष्णव को नवागढ़ से चांपा, निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय को थाना प्रभारी जांजगीर से रक्षित केंद्र भेजा गया है।

वहीं निरीक्षक मनोहर लाल सिन्हा को पामगढ़ से बलौदा, निरीक्षक सावन कुमार सारथी को चौकी प्रभारी नैला से पामगढ़ तथा निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव को बलौदा से शिवरीनारायण का थाना प्रभारी बनाया गया है।इसी तरह निरीक्षक सुभाष चौबे को सारागांव से रक्षित केंद्र, निरीक्षक कमलेश कुमार शैलेन्द्र को यातायात शाखा से नवागढ़ थाना प्रभारी तथा निरीक्षक राकेश कुमार सूर्यवंशी को यातायात शाखा से सारागांव थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।उप निरीक्षकों में उप निरीक्षक सरम कुमार चौहान को थाना जांजगीर से हटाकर पुलिस सहायता केंद्र राहिते में लाइन अटैच किया गया है। उप निरीक्षक भवानी सिंह चौहान को थाना जांजगीर से चौकी प्रभारी नैला तथा उप निरीक्षक दादूराम सिंह को थाना चांपा से रक्षित केंद्र भेजा गया है। इसी तरह सहायक उप निरीक्षकों में रामप्रसाद बघेल को पुलिस सहायता केंद्र राहौद से थाना बिर्रा, अरुण कुमार सिंह को थाना चांपा से थाना जांजगीर, भुवनेश्वर सिंह राठौर को नवागढ़ से चांपा, कृष्ण कुमार कोसले को सारागांव से चौकी नैला , लखबीर सिंह को जांजगीर और नाजिर हुसैन, सुरेंद्र सिंह क्षत्रिय , बलवंत धृतलहरे को रक्षित केंद्र से क्रमशः नवागढ़, यातायात शाखा और चांपा भेजा गया है।आरक्षकों में आर. 836 ईश्वरी कुमार राठौर को बलौदा से रक्षित केंद्र, आर. 407 हेमंत बघेल को रक्षित केंद्र से नवागढ़, जबकि आर. 704 हेमंत साहू, आर. 297 रमेश भारद्वाज और आर. 243 संजय टंडन को थाना नवागढ़ से कोटमी सोनार पदस्थ किया गया है।

खास खबर

बेहतर मौसम और सुव्यवस्थित खरीदी व्यवस्था से खुश किसान - किसन बंजारे ने बेचा 145 क्विंटल धान

कोरबा। कोरबा ब्लॉक के ग्राम करुमौहा निवासी किसान किसन बंजारे के चेहरे पर आज संतोष और प्रसन्नता साफ झलक रही थी। उन्होंने धान उपार्जन केंद्र नकटीखार में 145 क्विंटल धान बेचा। लगभग 8 एकड़ भूमि में खेती करने वाले किसन बंजारे ने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने 150 क्विंटल धान बेचा था। किसन बंजारे के अनुसार, इस वर्ष समय पर हुई बारिश से उनकी खेती बेहतर रही और जितना धान बोया था, लगभग उतनी ही मात्रा में फसल प्राप्त हुई।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के लिए लगातार राहत और सहयोग दिया जा रहा है। उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था, पारदर्शी प्रक्रिया और समय पर खरीदी होने से किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही। किसानों को बस टोकन लेकर निर्धारित दिन पहुँचने की आवश्यकता है। केंद्र में बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी सुनिश्चित की गई हैं। सरकार की सुव्यवस्थित धान खरीदी व्यवस्था और बेहतर मौसम ने किसान किसन बंजारे के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।

जनदर्शन में करण और मीना को मिला व्हीलचेयर

० कुल 86 आवेदन प्राप्त हुए

कोरबा। कलेक्टर जनदर्शन में लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका त्वरित समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में आज कलेक्टर जनदर्शन के दौरान ग्राम पोटापानी, जनपद पंचायत पाली के निवासी करण श्रीवास एवं मीना श्रीवास द्वारा व्हीलचेयर की मांग प्रस्तुत की गई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के समक्ष अपनी आवश्यकता रखते ही मामले पर तत्काल संज्ञान लिया गया। समाज कल्याण विभाग, कोरबा द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई और जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश नाग तथा अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल, सयुंक्त कलेक्टर श्री ओंकार यादव, डिप्टी कलेक्टर श्री तुलाराम भारद्वाज की उपस्थिति में दोनों हितग्राहियों को व्हीलचेयर प्रदान की गई। कलेक्टर जनदर्शन में कुल 86 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन में आमनागरिको की समस्याओं को सुना गया।

जिला स्तरीय स्पोर्ट्स मीट आयोजित

कोरबा, । युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबद्ध मेरा युवा भारत कोरबा (नेहरू युवा केंद्र संगठन) द्वारा जिला स्तरीय स्पोर्ट्स मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन दिनेश चंद्र यादव (उप निदेशक, मेरा युवा भारत छत्तीसगढ़) के निर्देशन में 27 एवं 28 दिसंबर को विद्युत गृह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1, सीएसईबी कोरबा परिसर में संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम अंतर्गत पुरुष वर्ग में कबड्डी, गोला फेंक एवं 800 मीटर दौड़, जबकि महिला वर्ग में रस्साकसी, गोला फेंक एवं 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

साय सरकार की धान खरीदी व्यवस्था से किसानों में संतोष

किसान-हितैषी नीतियों का प्रतिफल : खेती बनी लाभ का आधार

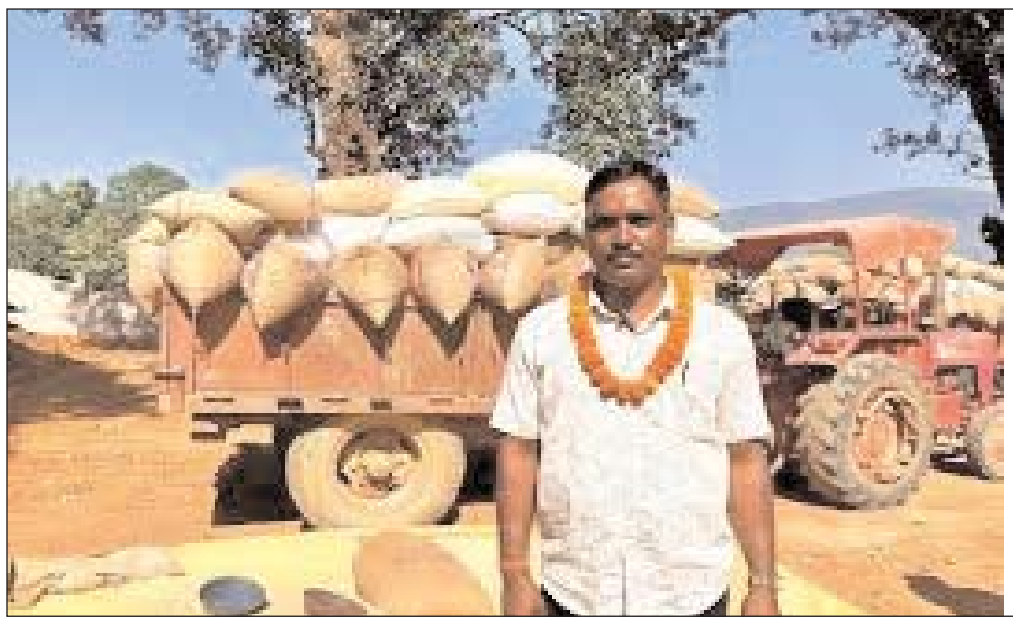

कोरबा संवाददाता।

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसान वर्ग को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा निरंतर ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश में संचालित धान खरीदी व्यवस्था न केवल देश में सर्वाधिक समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है, बल्कि टोकन से लेकर अंतिम विक्रय और भुगतान तक किसानों को हर स्तर पर सुविधा, पारदर्शिता और सम्मान का अनुभव करा रही है।

राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि किसान अपनी उपज बेचने के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा, लंबी प्रतीक्षा या अव्यवस्था का सामना न करें। इसी उद्देश्य से समिति स्तर पर टोकन व्यवस्था, मंडियों में सुव्यवस्थित प्रबंधन, सहयोगी वातावरण और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। इन प्रयासों का सकारात्मक असर अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।

कोरबा जिले के कनकी धान मंडी में ग्राम गुमिया निवासी कृषक श्री जमुना प्रसाद बियार इस सुगठित व्यवस्था के प्रत्यक्ष लाभार्थी बने। श्री बियार ने अपनी लगभग 06 से 07 एकड़ कृषि भूमि में उपजाए गए 104 क्विंटल धान का विक्रय मंडी में किया। उन्होंने बताया कि ऑफलाइन समिति के माध्यम से उन्हें बिना किसी लाइन में लगे और बिना किसी परेशानी के समय पर टोकन प्राप्त हो गया, जिससे मंडी में धान विक्रय की प्रक्रिया सहजता से पूरी हुई। बियार ने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने 110 क्विंटल धान का विक्रय किया था और उस समय भी शासन की व्यवस्था संतोषजनक रही। सरकार द्वारा सर्वाधिक समर्थन मूल्य दिए जाने से उन्हें अपनी फसल का उचित और लाभकारी मूल्य मिलने का पूरा भरोसा है। उनके अनुसार, वर्तमान व्यवस्था ने खेती को केवल आजीविका का साधन ही नहीं, बल्कि सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य का आधार बनाया है। धान खरीदी की पारदर्शी और किसान-मैत्री व्यवस्था से न केवल किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। समय पर खरीदी, स्पष्ट प्रक्रिया और सहयोगपूर्ण वातावरण ने किसानों में शासन के प्रति विश्वास को और सुदृढ़ किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार की यह पहल स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राज्य सरकार किसानों के श्रम का सम्मान करने, उनकी आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। धान खरीदी की यह सुव्यवस्थित प्रणाली छत्तीसगढ़ में सुशासन, पारदर्शिता और किसान कल्याण की मजबूत नींव को दर्शाती है।

बालको द्वारा आयोजित किसान मेला से कृषि नवाचार को मिला बढ़ावा

कोरबा-बालकोनगर ।

वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने किसान दिवस के अवसर पर जिले के बेला और सोनगुढ़ा गांव में किसान मेला-2025 का आयोजन किया। इस मेले में 40 गांवों से आए 750 से अधिक किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में तकनीकी विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि और कृषि उद्यमी भी शामिल हुए। यह मेला किसानों के लिए आधुनिक खेती और सतत आजीविका से जुड़ी जानकारी साझा करने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित हुआ।

बालको ने यह आयोजन बायफ, सतत आजीविका एवं विकास संस्थान के सहयोग से किया। मेले में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन और फसल बीमा से जुड़ी आधुनिक तकनीकों पर चर्चा और प्रदर्शन किए गए। बालको की 'मोर जल मोर माटी' परियोजना के तहत किसानों को वितरित किए गए कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई। नकटीखार स्थित हाई-टेक नर्सरी से जुड़े स्टॉल में गुणवत्तापूर्ण पौधों की जानकारी दी गई।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के स्टॉल में किसानों को समूह बनाकर काम करने और बाजार से जुड़ने के लाभ बताए गए। इसके अलावा मारुत ड्रोन, क्रॉम्पटन मोटर, बिड़ला पाइप, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के स्टॉल्स के माध्यम से आधुनिक तकनीक, सिंचाई समाधान, सरकारी योजनाओं और कृषि आधारित स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई।

बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री राजेश कुमार ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा में किसानों की भूमिका बहुत अहम है। बालको में हम केवल तकनीक या प्रशिक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किसानों को आय के नए अवसर और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रहे हैं। 'मोर जल मोर माटी' जैसी पहल के जरिए हम कृषि, बागवानी और पशुपालन को लाभकारी आजीविका के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं।

रोगबहरी गांव के किसान अर्जुन कंवर ने कहा बताया कि बालको के सहयोग से मेरी खेती में बड़ा बदलाव आया है। प्रशिक्षण से मुझे बेहतर खेती, उत्पादन को बढ़ाना और लागत में कमी के साथ आदि जरूरी बातें सीखने को मिला। इस साल बेहतर खेती अपनाने के लिए मुझे सम्मान भी मिला, जिससे मुझे और आगे सीखने व दूसरे किसानों को प्रेरित करने की ताकत मिली।

मोर जल मोर माटी परियोजना जल प्रबंधन, बहुफसली खेती, बागवानी और पशुपालन को बढ़ावा देती है। यह परियोजना 3,200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 8,000 से ज्यादा किसानों तक पहुंच चुकी है। अब तक 6,000 से अधिक किसानों ने आधुनिक खेती के तरीके अपनाए हैं, जिससे उनकी आमदनी और उत्पादन में वृद्धि हुई है। लगभग 25 प्रतिशत लाभार्थी युवा किसान हैं, जो यह दिखाता है कि खेती को आजीविका के रूप में अपनाने में युवाओं की रुचि बढ़ रही है।

सरकारी योजनाओं और संस्थागत सहयोग से किसानों को जोड़कर बालको ग्रामीण आजीविका को मजबूत कर रहा है और छत्तीसगढ़ में टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा दे रहा है। यह पहल दिखाती है कि ज्ञान, नवाचार और सहयोग से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

ICAR–NIBSM, रायपुर में स्वच्छता पखवाड़ा

ICAR–नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, रायपुर ने वैज्ञानिकों, कर्मचारियों, छात्रों, किसानों, युवाओं और स्थानीय समुदायों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक स्वच्छता पखवाड़ा (16-31 दिसंबर 2025) का आयोजन किया। इस अभियान में स्वच्छता शपथ, सफाई अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम, कचरे से धन जागरूकता, प्लास्टिक कचरा श्रमदान, ग्राम संपर्क, किसान दिवस समारोह, हस्ताक्षर अभियान, प्लॉगिंग कार्यक्रम, वॉकथॉन और सामुदायिक लामबंदी गतिविधियाँ शामिल थीं। इन पहलों ने स्वच्छ भारत मिशन के विज़न के अनुरूप स्वच्छता, स्थायी स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के बारे में जागरूकता को मजबूत किया। साथ मिलकर, हम एक स्वच्छ, हरित और स्थायी भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) भारत में आईस्टेंट के साथ पहली 3डी फ्लेक्स एक्सस एंजियोग्राफी की

एजेंसी। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) के नेत्र रोग विभाग ने भारतीय चिकित्सा जगत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए उन्नत इमेजिंग तकनीक और न्यूनतम चीर-फाड़ वाली ग्लूकोमा सर्जरी को मिलाकर भारत में पहली बार आईस्टेंट के साथ 3डी फ्लेक्स एक्सस एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक संपन्न की है। नए स्टैंड-माउंटेड स्पेक्ट्रालिस सिस्टम और अत्याधुनिक 3डी ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप से संचालित यह अभूतपूर्व प्रक्रिया सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवाओं को वैश्विक नेत्र चिकित्सा देखभाल में अग्रणी स्थान पर रखती है। ग्लूकोमा, जो अपूरणीय अंधापन का एक प्रमुख कारण है, अपनी धीमी प्रगति के कारण लंबे समय से चिकित्सकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है।

कोयला हेराफेरी मामला : 3 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 13 पकड़े गए

कोरबा लोकशक्ति।

जिले में कोयला हेराफेरी के एक बड़े मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस प्रकरण में अब तक कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला गेवरा खदान से निजी कंपनी के लिए भेजे गए कोयले की अवैध हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए नए आरोपियों में सूरज खांडे, जगदेव भास्कर और राहुल वस्त्रकार शामिल हैं। इनमें से एक आरोपी सुपरवाइजर, दूसरा पेट्रोलिंग टीम का सदस्य और तीसरा ट्रेलरों में लगे जीपीएस सिस्टम को हटाने व तकनीकी छेड़छाड़ करने में विशेषज्ञ बताया जा रहा है। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ कोयला हेराफेरी, धोखाधड़ी और तकनीकी छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

साइडिंग पर कोयला डंप किए बिना जमा करते थे टीपी

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी जयरामनगर साइडिंग पर कोयला डंप करने के बजाय केवल टीपी (ट्रांसपोर्ट परमिट) जमा कर देते थे और कोयले को दूसरी जगह भेजकर अवैध रूप से खपा देते थे। इस तरीके से अब तक करीब 365 टन कोयले की हेराफेरी की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख 76 हजार रुपये बताई जा रही है। मामले में उपयोग किए गए 6 ट्रेलर भी पुलिस ने जब्त किए हैं।

भाजपा द्वारा मनरेगा का नाम बदलना राष्ट्रपिता का अपमान : सांसद ज्योत्सना महंत

कोरबा संवाददाता।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में रविवार को कोरबा जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) ने कटघोरा विधानसभा के ग्राम जवाली में एक दिवसीय विशाल धरना-प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने किया।

'मोदी की गारंटी' बनाम 'रोजगार की गारंटी' - प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सांसद ज्योत्सना महंत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, ÷कांग्रेस ने बापू के नाम पर ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं को रोजगार की कानूनी गारंटी दी थी। सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे कानून बनाकर गरीबों को हक दिया, लेकिन भाजपा अब बापू का नाम हटाकर उनका अपमान कर रही है। भाजपा केवल 'मोदी की गारंटी' की बात करती है, जबकि कांग्रेस ने काम की गारंटी दी थी।

सीडब्ल्यूसी के फैसले पर 24 घंटे में अमल सांसद महंत ने अपनी सक्रियता का परिचय देते हुए बताया कि शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ सड़क पर उतरने का निर्णय लिया गया था। इस फैसले पर त्वरित अमल करते हुए महज 24 घंटे के भीतर कोरबा की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया।

भविष्य में योजना बंद होने की आशंका - सांसद ने अंदेशा जताया कि भाजपा सरकार धीरे-धीरे योजनाओं के नाम बदलकर उनके मूल उद्देश्य को खत्म कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसी तरह नाम बदलने का सिलसिला जारी रहा, तो आने वाले समय में भाजपा इस जनहितैषी योजना को पूरी तरह बंद भी कर सकती है।

नेताओं की रही मौजूदगी

इस अवसर पर पीसीसी के सँयुक्त महामंत्री हरीश परसाई, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम कंवर, जिला अध्यक्ष मनोज चैहान, तनवीर अहमद, पोषक दास महंत, गोरेलाल यादव, दिलीप सिंह, किरण चैरसिया, तारकेश्वर मिश्रा, विशाल शुक्ला, प्रदीप अग्रवाल, सरपंच श्रीमती दिलेश कंवर, जनपद सदस्य फूलचंद कश्यप, सूरज दास मानिकपुरी, हीरालाल यादव, भुनेस्वरी दास, मुन्ना पाठक, भरत मिश्रा, राजकुमार मिश्रा, रहमान खान निक्कू कुकरेजा, राकेश अग्रवाल, गुलशन जायसवाल, देवेन्द्र खरे, राजकुमार श्रीवास, कमल बेलदार, मानसिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।

सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से: कलेक्ट्रेट चौक से निकलेगी हेलमेट बाइक रैली

माहभर चलेंगे जागरूकता कार्यक्रम

रायपुर (संवाददाता)।

सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और सुरक्षित आवागमन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह 2026 का आयोजन 1 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के सामने से हेलमेट बाइक रैली के माध्यम से किया जाएगा।

यह जानकारी यातायात पुलिस रायपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। रैली में पुलिस, जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक शामिल होंगे। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी और हेलमेट पहनने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा।

यातायात जागरूकता के लिए होंगे विविध आयोजन

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, एनएचएआई, नगरीय

प्रशासन सहित एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड और स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता रहेगी।

यातायात पुलिस रायपुर द्वारा सड़क सुरक्षा माह के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित हैं: चौक-चौराहों पर यातायात नियमों का पालन करने वाले नागरिकों का सम्मान

सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले गुड सेमेरिटन का सम्मान। शैक्षणिक संस्थानों में यातायात प्रशिक्षण कार्यक्रम

शहर के प्रमुख चौराहों पर फ्लैक्स और होर्डिंग्स

बस, ऑटो और ई-रिक्शा में जागरूकता बैनर व पोस्टर

ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता रथ, पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट और नुक्कड़ नाटक

ऑटो व ई-रिक्शा चालकों के लिए प्रशिक्षण एवं नेत्र/स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

व्यवसायिक वाहन चालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर । एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स द्वारा चौराहों पर जागरूकता अभियान।

स्कूल बस चालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम । स्कूलों में रंगोली, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता ।

टोल प्लाजा पर भारी वाहनों के चालकों को समझाइश । स्मार्ट सिटी के पीए सिस्टम, एलईडी और वीएमएस बोर्ड पर यातायात संदेश ।

मॉल, सिनेमाघरों और मल्टीप्लैक्स में जागरूकता वीडियो । इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्लोगन और प्रचार समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण ।

यातायात पुलिस की अपील

रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित यातायात के लिए नियमों का पालन करें। नशे की हालत में वाहन न चलाएं, तेज गति से वाहन न चलाएं, दोपहिया वाहन पर हेलमेट अवश्य पहनें, दोपहिया में केवल दो सवारी ही बैठाएं और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं।

स्वास्थ्य शिविर से लौटते समय डॉक्टर पर हमला, मामला दर्ज

संवाददाता

कोरबा जिले के गेवरा-दीपका क्षेत्र में स्थित नेहरू शताब्दी अस्पताल (एनसीएच) गेवरा के चिकित्सक डॉ. अर्पण विश्वास पर सोमवार को हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर डॉ. विश्वास ने हरदीबाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रलिया में सीएसआर के तहत एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर के दौरान इलाज के लिए पहुंचे गांव के रामनारायण पटेल को डॉ. अर्पण विश्वास ने लाइन में खड़े होकर उपचार कराने की बात कही। इस पर रामनारायण पटेल ने आपत्ति जताई और कथित रूप से बाद में देख लेने की धमकी दी।

शिविर से लौटते समय हमला आरोप है कि शिविर समाप्त होने के बाद जब डॉक्टर, अस्पताल स्टाफ और एम्बुलेंस कर्मी वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में रामनारायण पटेल, नीरज पटेल और उनके दो अन्य साथियों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने डॉ. अर्पण विश्वास के साथ गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से मारपीट की। इस हमले में डॉक्टर की आंख, सीने और पीठ में चोटें आई हैं।

डॉक्टर ने भागकर बचाई जान

घटना के बाद डॉक्टर और स्टाफ किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकले और दीपका थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। हरदीबाजार थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115 (2), 351(3) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय कार्य पर 2 अधिकारी एवं 6 कर्मचारी सम्मानित, एसएसपी दुर्ग ने किया पुरस्कृत

दुर्ग । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग विजय अग्रवाल (भापुसे) द्वारा उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम दिनांक 29 दिसंबर 2025 को पुलिस कंट्रोल रूम, सेक्टर-06 भिलाई में आयोजित किया गया।

एसएसपी दुर्ग द्वारा थाना नेवई एवं थाना भिलाई नगर के प्रकरणों में प्रभावी विवेचना एवं सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय से आरोपियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुल 02 अधिकारियों एवं 06 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।थाना नेवई के अपराध क्रमांक 162/2024, धारा 307, 120-बी, 34 भादवि (हत्या के प्रयास) के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाए जाने पर विवेचक उप निरीक्षक सुरेन्द्र तारम एवं प्रधान आरक्षक सूरज पाण्डेय, भागवत वर्मा तथा आरक्षक रवि बिसाई, ओमप्रकाश श्रीवास एवं विनय कुमार को नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

इसी प्रकार थाना भिलाई नगर के अपराध क्रमांक 484/2025, धारा 20(ख) नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने पर विवेचक उप निरीक्षक मन्नूलाल यादव तथा प्रधान आरक्षक भागवत वर्मा, रोशन भुवाल एवं आरक्षक ओमप्रकाश श्रीवास, विनय कुमार एवं राजेश चन्द्रौल को नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने सभी सम्मानित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार निष्ठा, ईमानदारी एवं कर्तव्यपरायणता के साथ कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया।

सेवानिवृत्त एसीएस श्री एम. के. राउत ने प्रोजेक्ट दधीचि के तहत नेत्र दान करने हेतु नेहा झा को किया सम्मानित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में जिला प्रशासन रायपुर द्वारा चलाया जा रहा प्रोजेक्ट 'दधीचि' अब समाज में मानव सेवा का प्रतीक बन रहा है। इस अनूठी पहल ने अंगदान को लेकर लोगों, विशेषकर युवाओं में नई जागरूकता पैदा की है। अब तक जिले में 63 लोगों ने अंगदान कर इस अभियान को समर्थन दिया है। इसका उद्देश्य शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों को अंगदान के लिए प्रेरित करना है। इस कड़ी में आज पीडब्ल्यूडी विभाग में सहायक ग्रेड 3 श्रीमती नेहा झा ने एक प्रेरणादायक कदम उठाते हुए नेत्र दान करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के सीईओ एवं सेवानिवृत्त एसीएस श्री एम. के. राउत एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने उन्हें सम्मानित करते हुए शॉल एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया। श्रीमती झा ने कहा की मैं प्रोजेक्ट दधीचि के तहत अपना नेत्र दान कर रही हूँ ताकि मेरे मृत्यु के बाद मेरा नेत्र किसी के काम आ सके। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आमजनों से अपील की कि वे आगे आकर अंग एवं देहदान के इस महान कार्य में भागीदार बनें। इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

श्रीमती झा ने कहा की मैं प्रोजेक्ट दधीचि के तहत अपना नेत्र दान कर रही हूँ ताकि मेरे मृत्यु के बाद मेरा नेत्र किसी के काम आ सके।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने रचा आवास क्षेत्र में नया कीर्तिमान

रायपुर । छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने वर्ष 2025 में आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के विक्रय के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंडल द्वारा जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच कुल 4689 संपत्तियों का विक्रय किया गया, जिनका कुल मूल्य 1022 करोड़ रुपये से अधिक है। यह छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के गठन के बाद अब तक का सर्वाधिक वार्षिक विक्रय है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के नेतृत्व में मंडल द्वारा किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने की दिशा में योजनाबद्ध एवं प्रभावी कार्य किया जा रहा है, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम इस अभूतपूर्व सफलता के रूप में सामने आया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रारंभ से ही समाज के कमजोर एवं निम्न आय वर्ग को प्राथमिकता दी जाती रही है। अब तक निर्मित कुल आवासों में लगभग 70 प्रतिशत आवास कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए बनाए गए हैं। विगत पांच वर्षों में जहां मंडल द्वारा औसतन 1387 संपत्तियों का प्रतिवर्ष विक्रय हुआ और औसत मूल्य लगभग 262 करोड़ रुपये रहा, वहीं वर्ष 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 4689 संपत्तियों एवं 1022 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह मंडल की कार्यप्रणाली में हुए सुधार, नीतिगत सरलीकरण और आम नागरिकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। विगत एक वर्ष के दौरान शासन द्वारा लागू की गई ओटीएस-2 (वन टाइम सेटलमेंट) योजना के तहत हितग्राहियों को 30 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप 1452 संपत्तियों का विक्रय हुआ। इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 220.16 करोड़ रुपये रहा, जिससे मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के बड़ी संख्या में नागरिकों को सीधा लाभ मिला। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर इस वर्ष 23 से 26 नवंबर 2025 तक रायपुर के बीटीआई ग्राउंड, शंकर नगर में आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला 2025 भी अत्यंत सफल रहा। इस मेले के दौरान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 26 जिलों में 2080 करोड़ रुपये की लागत वाली 56 नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। साथ ही मेले के दौरान ही 305 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का विक्रय हुआ, जिससे मंडल की योजनाओं के प्रति आमजन का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2025 में 1022 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों का विक्रय एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सरकार की जनहितैषी नीतियों और आम नागरिकों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव तथा मंडल के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस सफलता के लिए बधाई दी।

नववर्ष कार्यक्रम के लिए होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फार्म हाउस और बार संचालकों को दिशा-निर्देश जारी

पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ली महत्वपूर्ण बैठक

रायपुर । नववर्ष के आगमन को देखते हुए राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य सोमवार 29 दिसंबर 2025 को पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने सिविल लाइन स्थित सी-04 भवन के सभाकक्ष में शहर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फार्म हाउस और बार संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में नववर्ष के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने संचालकों को स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया कि नववर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति के दौरान कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या, आमंत्रित सेलिब्रिटी और कार्यक्रम की प्रकृति की पूरी जानकारी पुलिस को देना आवश्यक होगा। साथ ही सभी होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फार्म हाउस एवं बार में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि नववर्ष के दौरान माननीय न्यायालयों द्वारा निर्धारित ध्वनि मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। किसी भी कार्यक्रम में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में यातायात व्यवस्था को लेकर भी खास निर्देश दिए गए। संचालकों को कहा गया कि उनके प्रतिष्ठानों के बाहर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्य मार्गों या सर्विस रोड पर वाहन खड़े कर यातायात बाधित करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आउटर क्षेत्र के सभी बार, होटल, ढाबा और फार्म हाउस को नववर्ष की रात 12:00 से 12:30 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद करने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने शराब परोसने को लेकर भी सख्त चेतावनी दी। बिना वैध लाइसेंस के शराब परोसने या आबकारी अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों या वाहनों के भीतर बैठकर शराब सेवन कराने पर भी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई तय है। एसएसपी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की हुड़दंग, अव्यवस्था या नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं होना चाहिए। यदि सूखा नशा या अन्य अवैध पदार्थ पाए जाते हैं तो न केवल कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि संबंधित संस्थान का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। उन्होंने संचालकों को स्वयं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और पर्याप्त सुरक्षा गार्ड रखने के निर्देश दिए। साथ ही क्षमता से अधिक पास जारी न करने की हिदायत दी गई ताकि भीड़ और अव्यवस्था से बचा जा सके। पुलिस प्रशासन ने यह भी जानकारी दी कि 31 दिसंबर 2025 को रायपुर पुलिस द्वारा वीआईपी रोड सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने होटल-बार संचालकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी नियमों का पालन कर नववर्ष को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जाए, ताकि शहर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम डी.आर. पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक ईशु अग्रवाल (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक क्राइम संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवांगन, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन रमाकांत साहू, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा वीरेन्द्र चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

विशेष गहन पुनरीक्षण : राजनैतिक दलों की बैठक लेकर प्राप्त दावा-आपत्ति की दी गई जानकारी

कवर्धा । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 में दिए गए निर्देशानुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पण्डरिया एवं कवर्धा द्वारा आज मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित कर आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों को अवगत कराते हुए प्राप्त दावा-आपत्ति की जानकारी दी गई। अब तक विधानसभा क्षेत्र 71-पण्डरिया में 114 फार्म-6, 0 फार्म-7 एवं 35 फार्म-8 तथा विधानसभा क्षेत्र 72-कवर्धा में 170 फार्म-6, 02 फार्म-7 एवं 42 फार्म-8 प्राप्त हुआ है। बैठक में बताया गया कि वे सभी नागरिक जिनकी उम्र अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष अथवा ज्यादा हो वे सभी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फार्म-06 में आवेदन कर सकते हैं। फार्म-07 में मतदाता सूची से नाम विलोपन के लिए एवं फार्म-08 में स्थानांतरण, संशोधन, डुप्लीकेट ईपिक एवं विकलांगता का चिन्हांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदक फार्म में मोबाईल नंबर एवं ई-मेल का उल्लेख करते हुए आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर पावती प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त नागरिक स्वयं अपने मोबाईल में वोटर हेल्पलाईन मोबाईल एप से आवेदन कर सकते हैं।

अंबिकापुर में 4.8 डिग्री से जमा छत्तीसगढ़, रायपुर 12 डिग्री पर ठिठुरा, उत्तर-मध्य जिलों में शीत लहर का अलर्ट

रायपुर । छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में अगले 24 घंटों तक एक-दो स्थानों पर शीत लहर चलने की संभावना जताई गई है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में अगले 24 घंटों तक शीत लहर चलने की संभावना है। प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2=3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। जगदलपुर में सबसे अधिक और अंबिकापुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। रायपुर में 30 दिसंबर को कुहरा छाए रहने और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ में शीत लहर की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीत लहर का असर देखने को मिल सकता है। खासकर सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं लोगों को सतर्क रहने का संकेत दे रही हैं।

जगदलपुर सबसे गर्म, अंबिकापुर सबसे ठंडा

प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.8डिग्री अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। इससे साफ है कि उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड का असर ज्यादा बना हुआ है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि ठंड को देखते हुए बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

अगले दो दिनों के बाद भी प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है. ठंड धीरे-धीरे कम हो सकती है, लेकिन सुबह-शाम ठिठुरन बनी रह सकती है।

पीएम-उषा मद में अनियमितता पर शासन का सख्त रुख, लोहराकोट कालेज के प्राचार्य और पिथौरा कॉलेज के चार सहायक प्राध्यापक निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिला के शासकीय महाविद्यालय लोहराकोट के प्राचार्य और पिथौरा के चार सहायक प्राध्यापकों को सामग्री क्रय से जुड़े गंभीर आर्थिक अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार प्राचार्य डॉ. एस.एस. तिवारी पर पीएम-उषा मद के अंतर्गत आवंटित राशि में गड़बड़ी तथा वित्तीय नियमों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोष पाया गया है।इसी तरह पिथौरा महाविद्यालय में पीएम-उषा मद से प्राप्त राशि के अंतर्गत मिड-डे के दौरान जेम पोर्टल के माध्यम से किए गए क्रय में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 एवं संशोधित 2025 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। प्रारंभिक जांच में यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन के दायरे में पाया गया है। निलंबित किए गए सहायक प्राध्यापकों में डॉ. सीमा अग्रवाल, डॉ. हरभजन सिंह विशाल, पीठ सिंह ठाकुर एवं डॉ. एस.एस. दीवान सभी शासकीय महाविद्यालय पिथौरा के नाम शामिल हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत की गई है। निलंबन अवधि के दौरान सभी का मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा कार्यालय, रायपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। प्रकरण में विभागीय जांच की कार्यवाही पृथक से की जाएगी। यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है। शासन की इस कार्रवाई को शासकीय संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कुपोषण मुक्ति की दिशा में सफल रहा मिशन गोद अभियान,

जनभागीदारी से जिले में 20 प्रतिशत बच्चों को मिली कुपोषण से मुक्ति

रायपुर । बालोद जिला प्रशासन द्वारा गंभीर कुपोषित बच्चों को पौष्टिक भोजन समुचित उपलब्धता एवं उनके उचित देखभाल सुनिश्चित कर उन्हें सामान्य श्रेणी में लाने हेतु शुरू की गई मिशन गोद अभियान बालोद के परिणामों ने सभी को चौंका दिया। बालोद जिले के गंभीर कुपोषित बच्चों में से 20.80 प्रतिशत बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिला दी गई है। यह अभियान जिले को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं कारगर अभियान सिद्ध हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा इस अभियान के अंतर्गत जिले के अति गंभीर कुपोषित बच्चों को समुचित पौष्टिक आहार एवं देखरेख के लिए समुचित राशि एवं अन्य जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, समाजसेवी संगठनों तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि मिशन गोद के अंतर्गत क्षेत्रीय सांसद, जिले के तीनों विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित जिले के सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारियों के अलावा जिले के सभी अधिकारियों को इन बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी दी थी। अतिरिक्त आहार राशि के लिए 4.48 लाख रूपये से अधिक हुए जमा बालोद जिले में 10 सितंबर से 10 दिसंबर तक जारी इस अभियान के अंतर्गत गोद लेने वाले सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन एवं अन्य जरूरी खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता के लिए न्यूनतम 500 रूपये की राशि जमा की। जिसके फलस्वरूप कुपोषित बच्चों के लिए अतिरिक्त आहार राशि के लिए 04 लाख 48 हजार रूपये से अधिक की राशि प्राप्त हो चूका है। जनप्रतिनिधियों ने 300 बच्चों को लिया गोद उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर से 10 दिसंबर तक जिले में 03 माह की समयावधि के लिए लागू इस अभियान के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों द्वारा कुल 300 गंभीर कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया था। जिसमें से 53 बच्चे सामान्य श्रेणी में आ गए हैं। इसी तरह जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा कुल 184 बच्चों को गोद लिया गया है। इसमें से वर्तमान में 51 बच्चे सामान्य श्रेणी में आ गए हैं। इसके अलावा जन सामान्य के द्वारा 180 बच्चों को गोद लिया गया है।

31 दिसंबर तक बंद स्कूल, दफ्तर, छत्तीसगढ़ में 4.50 लाख कर्मचारियों की हड़ताल से बढ़ी परेशानी

रायपुर । छत्तीसगढ़ में 4.50 लाख कर्मचारियों की तीन दिन की हड़ताल से दफ्तरों में काम काज पूरी तरह से ठप पड़ा है। बता दें कि 31 दिसंबर तक स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है। हड़ताल के चलते एक ओर जहां दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है तो वहीं स्कूलों को बंद करने की घोषणा से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले यह हड़ताल हो रहा है। बता दें कि फेडरेशन ने महंगाई भत्ता, चार स्तरीय वेतनमान, 300 दिन का अर्जित अवकाश नकदीकरण सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।हड़ताल को सफल बनाने के उद्देश्य से फेडरेशन के पदाधिकारियों द्वारा 26 दिसंबर 2025 को जल संसाधन विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, तहसील कार्यालय, नगर निगम सहित विभिन्न शासकीय कार्यालयों में व्यापक जनसंपर्क किया गया। पदाधिकारियों ने कर्मचारियों को हड़ताल के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए इसमें सक्रिय सहभागिता का आग्रह किया। फेडरेशन ने 29 से 31 दिसंबर तक सभी कर्मचारियों से नेहरू चौक, बिलासपुर में स्थापित धरना पंडाल में उपस्थित होकर आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया है।

रायपुर जिले में हुई 1 लाख 59 हजार 527.60 क्विंटल धान खरीदी

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश में जिले के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। जिले में आज 2954 किसानों से 1 लाख 59 हजार 527.60 क्विंटल धान की खरीदी की गई। इस प्रकार अब तक 71016 किसानों से 33 लाख 99 हजार 063.20 क्विंटल की खरीदी हुई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में धान खरीदी केन्द्रों में किसानों को आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों में धान बेचने को लेकर उत्साह है।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)